सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

.सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 05 मार्च, 2025 ई०

चतुर्दश सत्र — 14 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कार्यस्थगन है । दलित पर अत्याचार हो रहा है ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी, आप पुराने मेंबर हैं, आप जानते हैं कि कब उठाना है तो क्यों पहले उठ जाते हैं । बैठ जाइए । समय पर अपनी बात रखिएगा । बैठ जाइए । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सदन के मेंबर गोपाल रविदास जी को अपना अधिकार नहीं लेने दिया गया, विद्यालय के अध्यक्ष हैं और उनको शिलान्यास नहीं करने दिया गया और ऊपर से उनके ऊपर सामंती हमले हुए, गुंडों ने हमला किया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । समय पर अपनी बात उठाइएगा ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–2 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में ट्रांसफर हो गया है । अगली बार आपका जवाब दिया जायेगा । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानांतरित हो गया है, जब आएगा तो आपका जवाब दिया जाएगा । बैठ जाइए ।

अध्यक्ष : श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–3 श्री अरूण शंकर प्रसाद (खजौली)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, दूसरे प्रश्न का उत्तर अपलोड है तारांकित का । अल्पसूचित का उत्तर अपलोड नहीं था ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, इनका उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थल, प्रति एक लाख की आबादी पर 10.90 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ के राष्ट्रीय औसत के विरूद्ध बिहार राज्य में प्रति एक लाख की आबादी पर 4.54 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देश में राष्ट्रीय उच्च पथ की औसत लम्बाई 39. 90 किलोमीटर प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर के विरूद्ध बिहार राज्य में प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय उच्च पथ की औसत लम्बाई 63.24 किलोमीटर है ।

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में बढ़ोत्तरी हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु पथों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय,..

अध्यक्ष : पूरक है क्या ? पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी ही है माननीय मंत्री जी से कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति बिहार में एन0एच0 की कम है, तो उसको पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह तो कारण नहीं है कि भू–अर्जन में जो विलंब हो रहा है बिहार के अंदर उसके कारण हमारे एन0एच0 की लंबाई जितनी बढ़नी चाहिए वह नहीं पढ़ पा रही है इसलिए भू–अर्जन से ज्यादा...

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, ऐसी स्थिति नहीं है । माननीय सदस्य ने जिस ओर चिंता व्यक्त की है, मैं कुछ विषय सदन के सामने रखूंगा कि जो राष्ट्रीय उच्च पथ है उसमें हमारे यहां 2005 के समय में सिंगल लेन और इंटरमीडिएट लेन की संख्या की काफी थी, लेकिन आज हमारे पास जो 2005 में मात्र 1200 किलोमीटर टू–लेन की सड़कें थीं जब कि आज हमारे पास 2000 किलोमीटर की टू–लेन की सड़कें हैं । 2005 में केवल 800 किलोमीटर की टू–लेन की सड़कें थीं आज हमारे पास 2600 किलोमीटर की फोर लेन की सड़कें हैं । जहां हम एन0एच0 में अगर गुणवत्ता का कह सकते हैं, जो पॉपुलेशन के आधार

पर हमलोग भले उसमें पीछे हैं लेकिन जो टोटल एरिया है उसमें एन0एच0 की बढ़ोतरी हुई है । 2005 में एन0एच0 मात्र 3600 था आज 6000 किलोमीटर से ऊपर एन0एच0 भी हैं । इसके साथ–साथ जो टू–लेन और फोर–लेन की सड़कों के साथ–साथ सिक्स–लेन की सड़कें भी आईं । कई ऐसी योजनाएं भी आईं जिसमें बड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार ने एन0एच0 के माध्यम से दिया, उसमें भी लैंड एक्यूजीसन में जो बड़ी योजनाएं जैसे–आमस–दरभंगा, पटना–बेतिया, पटना–आरा–सासाराम, वाराणसी–कोलकाता, राम जानकी मार्ग बक्सर–चौसा ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको भी केंद्र सरकार ने योजनाएं दी हैं, केंद्र सरकार और एन0एच0 की अब यह रणनीति रही है कि अब हम एन0एच0 के अतिरिक्त ग्रीन फील्ड एलाइंमेंट में ज्यादा काम करेंगे, तो जो ग्रीन फील्ड एलाइंमेंट आया है उससे बिहार को कई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे मिले हैं उसके कारण भी एन0एच0 की जो संख्या है, उसके मानक के हिसाब से कमी आपको दिख रही है, लेकिन वह भी पॉपुलेशन के आधार पर है, एरिया के आधार पर नहीं है और माननीय सदस्य की जो चिंता है लैंड एक्यूजीशन को लेकर उसका भी हमलोगों ने हल निकाला है और बहुत जल्द उसमें और बढ़ोतरी होगी ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, बहुत साधारण है...

अध्यक्ष : बहुत विस्तार से मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं यह स्वीकार कर रहा हूं कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में एन0एच0 बिहार के अंदर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और हर तरह का सहयोग भी दिया है लेकिन मेरी चिंता यह है कि हमारे बिहार सरकार की जो एजेंसी है वह कहीं न कहीं इसमें काम करने में जो फिसड्डी रह रही है उसके कारण हमारे एन0एच0 का औसत जो आज से 20 वर्ष पहले था वही औसत आज भी कमोबेश बना हुआ है, हमारा औसत अन्य राज्यों की तुलना में नहीं बढ़ रहा है इसके लिए सरकार अपने तंत्रों को कैसे ठीक करेगी और मेरी जो दूसरी चिंता थी कि संभवतः भूमि अधिग्रहण के मामले में जो अड़चनें आ रही हैं जैसे– छपरा वाली सड़क है और आज तक वह रुका हुआ है और हम सब लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं तो उसके निदान के लिए सरकार ऐसे कौन–सी उपाय करेगी जो तीव्र गति से,...

अध्यक्ष : भाषण नहीं, पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जी महोदय । तीव्र गति से एन0एच0 विस्तार के लिए, तीव्र गति से एन0एच0 निर्माण के लिए सरकार कौन–सी कार्रवाई करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो विस्तार से बताया । विस्तार से तो बताए कि क्या–क्या कर रहे हैं, कितना था, कितना बढ़ गया और आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि बिहार के अंदर जो आबादी का घनत्व प्रति किलोमीटर है उसमें यह भी एक कठिनाई है और यहां संयोग से मुझे भी थोड़ी जानकारी है इसलिए मैंने आपको कह दिया । माननीय मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया है और अभी आपने देखा भी है कि बड़े पैमाने पर सड़कों की जो घोषणा हुई है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास कर रहे होंगे, माननीय मंत्री जी, बोलिए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा भी कि जो प्रगति यात्रा के माध्यम से अभी बड़े पैमाने पर सड़कों को माननीय मुख्मयंत्री जी ने लिया है । माननीय सदस्य की चिंता जो लैंड एक्यूजीशन को लेकर है उसका भी समाधान हमलोग निकाल रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर जो फॉरेस्ट के क्लीयरेंस हैं तो कई राज्यों ने फॉरेस्ट में वाटर बॉडी का जो बैंक है उसको अब फॉरेस्ट के लिए यूज करना शुरू किया है । हमलोग भी उसी पद्धति पर जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण जो मामले थे वह भी अब घट जाएंगे और लैंड एक्यूजीशन में जो इनके विषय हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारे किलोमीटर्स में संख्या भले हैं लेकिन अगर आप देखेंगे, आबादी के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि जो एरिया है उसके मानक के हिसाब से राष्ट्रीय औसत 39 किलोमीटर है, हम 60 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हैं, तो मेरा यह मानना है कि जो उनकी चिंता है उस पर हमलोग ध्यान देंगे और केंद्र सरकार से हमलोगों ने नए एन0एच0 के लिए अब सिफारिश भी करने जा रहे हैं ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–4 श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)</u>

अध्यक्ष : श्री मुकेश कुमार यादव । माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, आपको ही ट्रांसफर हुआ है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय...

अध्यक्ष : नगर विकास एवं आवास विभाग में आपका प्रश्न ट्रांसफर हुआ है । अगली बार जब नगर विकास एवं आवास विभाग का आएगा तब जवाब मिलेगा । बैठ जाइए । आपका प्रश्न ट्रांसफर हो गया है नगर विकास एवं आवास विभाग में ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे विभाग का है । अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब भी तैयार करके लाया हूं, माननीय सदस्य को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा ।

अध्यक्ष : मुकेश जी का ?

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : जी महोदय ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठिये । आप बोलिएगा । हम हैं न आपके लिए । आप क्यों बोल रहे हैं ? माननीय मंत्री जी, किनके प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं?

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : मुकेश जी का ।

अध्यक्ष : मुकेश जी का जवाब आपके विभाग से क्या मतलब है । अल्पसूचित है ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : जी महोदय । तीसरा नंबर है ।

अध्यक्ष : बताइए ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना द्वारा गंगा नदी पर 34 स्थानों पर नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच की जाती है प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नदियों के जल का घुलित ऑक्सीजन डीजॉल्व एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिकांश शहरों में मानकों के अधीन पाए गए हैं परंतु जीवाणुओं की संख्या यथा टोटल कोलीफॉर्म और फीकल कोलीफार्म की मात्रा औसत मानक से ज्यादा पाई गई है । इसका कारण शहरी क्षेत्रों से जनित होने वाले अनौपचारिक सीवेज मल–जल का प्रवाह है। गंगा नदी का जल जीवाणुओं की संख्या के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की गजट अधिसूचना संख्या–494, दिनांक–25.09.2000 के स्नान जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मापदंड नहाने के योग्य नदी की गुणवत्ता को धारण नहीं करते हैं । गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे बसे छोटे–बड़े नगरों के अनौपचारिक मल–जल गंगा में प्रवाहित होने के कारण नदियों के जल में जीवाणुओं की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है । सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत शहरों के जनित होने वाले सीवेज मल–जल के उपचार के लिए, मल–जल के उपचार संयंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बुडको, पटना द्वारा बनाई जा रही है ।

राज्य के किसी भी आद्यौगिक इकाई द्वारा बहिस्राव का निस्तारण गंगा नदी में नहीं किया जाता है, गंगा नदी की गुणवत्ता नियमित रूप से पर्षद द्वारा जांच की जाती है, गंगा जल की गुणवत्ता जलीय जीवों के लिए अनुकूल है । गत वर्ष–2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 से प्राप्त विश्लेषण

प्रतिवेदन के अनुसार विगत वर्षों में गंगा जल की गुणवत्ता में क्रमिक सुधार पाया गया है । (क्रमशः)

टर्न–2 / आजाद / 05.03.2025

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : (क्रमशः) राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के जल गुणवत्ता में सुधार हेतु गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में मल–जल उपचार संयंत्र ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है । पटना में चार निर्माण हो चुका है, बाढ़ में एक, मुंगेर में एक, सोनपुर में एक, सुल्तानगंज में एक, मनेर में एक, नवगछिया में एक, छपरा में एक, दानापुर में एक, फुलवारीशरीफ में एक का निर्माण हो चुका है । ऐसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 लगने हैं, कार्य प्रगति पर है । आशा है कि जब लग जायेगा तो जो फिकल कोलीफॉर्म है, वह भी कम हो जायेगा अध्यक्ष महोदय ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी अपने उत्तर में स्वीकार किये हैं कि गंगा नदी का जल स्तर प्रदूषित है । इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार जितनी भी राशि शहरों के नाले के पानी के शोधन में लगा रही है, वह निष्फल व्यय हो रहा है क्योंकि पटना में अनेकों बड़े नाले गंगा नदी को प्रदूषित करती है । अध्यक्ष महोदय, हम पानी भी लाये हैं गंगा जल का और इसकी जॉच करवा दीजिए विधान सभा की समिति से .....

अध्यक्ष : पानी का जॉच विधान सभा की समिति करेगी ? पूरक पूछिए, बिना अनुमति के कोई चीज दिखाईए मत । पूरक पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पूरक मेरा इसमें है कि सरकार इसके पानी की गुणवत्ता के लिए कब तक सुधार कर सकती है ताकि गंगा का पानी प्रदूषणमुक्त हो।

अध्यक्ष : आपने मंत्री जी का जवाब सुना नहीं है ?

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, 10 साल से इसपर गंगा नदी के पानी शुद्धता करने के लिए कार्य चल रहा है ......

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने इतना विस्तार से जवाब दिया है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : हुजूर, 10 साल से हो रहा है न, 10 साल से अभी तक क्या हुआ और अभी तक सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो विस्तार से बताया है कि कितने जगह सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, अभी भी कह रहे हैं कि मंत्री जी अपने ......

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : पूरक ही मेरा है कि माननीय मंत्री जी, कब तक इसकी शुद्धता करवा सकते हैं ?

(व्यवधान)

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को कहा .....

अध्यक्ष : बैठे–बैठे बोलने वाले का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है प्लीज ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 बनने हैं, रातों–रात सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता है । उसके बनने में कुछ समय लगता है । 32 बनने हैं, 13 बन गये हैं, 32 बन जायेंगे तो निश्चित तौर पर गंगा जल की शुद्धता में निरन्तर सुधार होगा ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक टाईम मुकर्रर नहीं किये हैं न , आपसे आग्रह है हुजूर कि विधान सभा की समिति बनाकर इसकी जॉच करवा दीजिए ।

अध्यक्ष : किसलिए ? काम हो रहा है, 13 बन गया है, 29 बनना है, समय तो लगेगा ही न ।

श्री मुकेश कुमार यादव : 10 साल से जॉच ही हो रहा है न, इसपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है न ।

अध्यक्ष : बैठ जाईए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मुकेश जी का प्रश्न जो है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया है, बहुत सही भी है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि जो बुडको काम कर रही है, उन्होंने कहा कि 32 जगहों पर काम चल रहा है । पिछले 5 साल से काम चल रहा है, वन विभाग, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की लड़ाई में पूरे बिहार में 32 जगहों पर ये रूकावट डाले हुए हैं और लगातार स्टीमेट बढ़ता जा रहा है । हम मधुबनी का उपमा देंगे, इनके द्वारा पी0डब्लू0डी0.....

अध्यक्ष : आप कहां चले जा रहे हैं, आप विभागीय मंत्री जी में लड़ाई लगवाना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं सर ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री समीर कुमार महासेठ : पूरक यही है कि गंगा को कब तक शुद्ध करेंगे, ये कार्य योजना कैसे बनायेंगे, पूरा नगर का पानी जाता है । भागलपुर तक में, इसका कार्य योजना ......

अध्यक्ष : बैठ जाईए । माननीय मंत्री ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने उत्तर में कहा कि हमारा काम जॉच करना है और नगर एवं आवास विभाग उसका निर्माण करा रही है और मैंने यह भी कहा कि रातों–रात नहीं बन सकता है । जिसकी चिन्ता माननीय सदस्य आज कर रहे हैं, सरकार उसपर पहले से चिन्ता करके योजना बनाकर के चरणवद्ध तरीके से काम कर रही है ।

अध्यक्ष : बैठ जाईए । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री रामप्रवेश राय जी । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0–173(श्री रामप्रवेश राय, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

1. ग्राम नेहरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पश्चिम जाने वाली पथः–इस पथ का वास्तविक नाम पिपरहिया से नेऊरी पथ के नाम से MMGSY योजना अन्तर्गत स्वीकृत एवं एकरारित है, जिसकी लम्बाई 1.230 किलोमीटर है । इस पथ का एकरारनामा संख्या–51/SBD/MMGSY/2020–21 है । कार्य प्रारंभ की तिथि 23.06.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–26.05.2021 है। इस पथ में 0.510 कि0मी0 में कार्य करा दिया गया है । शेष पथांश में ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण अवरुद्ध किया गया है एवं भूमि विवाद के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना में CWJC No-9140/2021 विचाराधीन है । माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के निर्णय के आलोक में पथ की मरम्मति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

2. NH–27 से देवापुर से होकर सारण बांध की तरफ जाने वाली पथः– इस पथ की लम्बाई 1.870 किलोमीटर है, जो नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत देवापुर से देवापुर हाई स्कूल के नाम से स्वीकृत एवं एकरारित है। 1.270 कि0मी0 में बिटुमीन कार्य की गई है। शेष पथांश में 0.60 किलोमीटर में बिटुमीन के स्थान पर PCC का प्रावधान करते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार की गई थी, जिसकी स्वीकृति प्राप्त है । शेष कार्य दिनांक–31.03.2025 तक पूर्ण करा ली जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए रामप्रवेश जी ।

श्री रामप्रवेश राय : माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो ठीक है माननीय मंत्री जी का, लेकिन इनके उत्तर में जो खंड–1 का उत्तर है–पिपरहिया से नेऊरी पथ के नाम से यह पथ है, इसका टेंडर हो गया था, काम भी लगा, काम भी बहुत हुआ है लेकिन कुछ जगहों पर विवाद के कारण काम बंद हो गया । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पटना उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है लेकिन मैं इनके संज्ञान में यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पटना उच्च न्यायालय ने इसपर निर्णय दे दिया है । आप विभाग से जानकारी करके जो शेष कार्य बाकी है, उस कार्य को कराने का कष्ट करें । इसको क्या करेंगे, इसके बारे में बोल दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : इसको जल्द से जल्द करा देंगे ।

अध्यक्ष : जल्द करा देंगे, अब बैठिए । श्री रामानुज प्रसाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–174(श्री रामानुज प्रसाद, सोनपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर दियारा पंचायत के प्रश्नगत बल्ली टोला स्थल गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित है।

प्रश्नगत स्थल पर नदी के तट से बसावट की न्यूनतम दूरी 15 मीटर है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के पास नदी तट का क्षरण हो रहा है।

स्थल के सुरक्षार्थ योजना प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । इस कार्य को आगामी बाढ़ पूर्व करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए रामानुज जी, माईक पर बोलिए ।

श्री रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है मेरे प्रश्न को, इसमें है कि करा लिया जायेगा तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसको जल्द करा दिया जाय, इसको कब तक करा देंगे, कटाव से मेरा गांव कट रहा है......

अध्यक्ष : आग्रह भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, यह दोनों काम कैसे होगा ?

श्री रामानुज प्रसाद : आग्रह करते हुए माननीय मंत्री जी से पूछ रहे हैं सर ।

अध्यक्ष : बैठ जाईए, माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

आप रामानुज जी के विरोधी हैं, उनका क्वेश्चन नहीं होने देना चाहते हैं, उनका जवाब होने देना नहीं चाहते हैं ? बोलिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो आपको देख रहे थे, आप भाई वीरेन्द्र जी को देखने में हैं .....

अध्यक्ष : क्या करें अपने आदमी हैं, उनको बार–बार देखना ही पड़ता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, रामानुज जी ने ठीक कहा है और मेरे उत्तर को अगर गौर से पढ़ लेते तो हमने कहा है, इन्होंने कहा है कि करा दिया जायेगा, आपने पूरक पूछा कि कब तक करा दिया जायेगा, उसका भी उत्तर उसी में लिखा हुआ है....

अध्यक्ष : बाढ़ से पहले ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आगामी बाढ़ से पूर्व । बाढ़ का सीजन जो जून–जुलाई होता है, उसके पूर्व करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तो हो गया, इतना बढ़िया जवाब किसी को मिलता है, यह तो केवल आपको ही मिल रहा है ।

श्री रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से पूर्व कह रहे हैं । कटाव जो है उत्तर में है कि कटाव जारी है, क्षरण जारी है और मात्र 15 मीटर दूर है बसावट से, इसलिए मैं बाढ़ से पहले, इस अवधि में हमारा गांव कट जायेगा, गरीबों का गांव है, मैं यह चाहता हूँ कि बाढ़ तक नहीं ले जाया जाय, अभी कार्य शुरू करा दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : बाढ़ तक जाकर के शुरू करने की बात हमने नहीं कही है, बाढ़ तक जाकर के हमने काम खतम करने की बात कही है और शुरू अब जल्दी ही होगा ।

अध्यक्ष : अब हो गया, श्री अजय कुमार जी ।

तारांकित प्रश्न सं0–175 (श्री अजय कुमार, बिभूतिपुर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग । यह ट्रांसफर हो गया है पंचायती राज विभाग में । जवाब है न ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : ट्रांसफर हो गया है ।

अध्यक्ष : आपके यहां ही हुआ है न । ग्रामीण कार्य विभाग से आपके यहां ट्रांसफर होकर गया है, आप अभी नहीं लाये हैं तो अगले बार दे दीजियेगा ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : ठीक है सर ।

श्री अजय कुमार : इसका क्या हुआ सर ?

अध्यक्ष : ट्रांसफर होकर गया है, जवाब आयेगा तब न ।

श्री अजय कुमार : कब आयेगा जवाब सर ?

अध्यक्ष : ऑटोमेटिक, जिस दिन यह होगा फिर से, अगले बुधवार को होगा या उसके अगले बुधवार को होगा ।

श्री अजय कुमार : ठीक है सर ।

तारांकित प्रश्न सं0–176 (श्री प्रणव कुमार, मुंगेर)

अध्यक्ष : श्री प्रणव कुमार, पूरक पूछिए ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ । अन्सर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : उत्तर नहीं मिला है आपको ?

श्री प्रणव कुमार : 10.30 बजे तक नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, जरा उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल निर्माण के 6 वर्षों के बाद वर्ष 2023 में रैयत मोहम्मद शकुन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में मुआवजा भुगतान हेतु परिवाद दायर किया गया । उक्त वाद में 13.08.2024 को रैयत

को मुआवजा भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया, पारित आदेश के आलोक में सतत् लीज पर भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव समाहर्त्ता, खगड़िया को समर्पित किया गया है । भुगतान हेतु जिला प्रशासन द्वारा दर निर्धारण की जा रही है । तदनुपरान्त रैयतों को मुआवजा की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : कर दिया जायेगा ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक दशक से ज्यादा हो गया है । अभी तक जिला प्रशासन का ध्यान किसानों के मुआवजा पर नहीं गया है । अतः हम चाहते हैं सदन के माध्यम से कि इसे अविलम्ब दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न–3 / पुलकित / 05.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–177 (श्री मुकेश कुमार यादव, बाजपट्टी)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पथ 02 पथों से संबंधित है–

1– प्रखंड बाजपट्टी पंचायत मधुबन बसहा पूर्वी वार्ड नं0–14 एस0एच0 रोड पुपरी सीतामढ़ी गेनपुर चौक से गेनपुर टोला तक– उक्त पथ में अवस्थित बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावटों के तहत मोबाईल ऐप से सर्वे करा लिया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0–91746 है। प्राथमिकता अनुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

2– प्रखंड नानपुर पंचायत भदियन वार्ड नं0–5 ग्राम– छोटा भदियन से शांति वन मंदिर तक– उक्त पथ में अवस्थित बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावटों के तहत मोबाईल ऐप से सर्वे करा लिया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0–86915 है । प्राथमिकता अनुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा उत्तर आया है और मंत्री जी ने स्वीकार किया है और मंत्री जी का जवाब है कि इसमें प्राथमिकता अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं ये हमारे जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं और सड़क विभाग के मंत्री

हैं। हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारे यहां जो चयनित सूची में मुख्यमंत्री अवशेष योजना में 10 योजना का चयन हुआ है । यह सड़क काफी जीर्णशीर्ण अवस्था में है । बरसात के समय लोगों का आना–जाना पूरी तरह बंद हो जाता है । इसलिए हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में करवा दें ।

अध्यक्ष : इस वित्तीय वर्ष में कितने दिन बचे हैं ?

श्री मुकेश कुमार यादव : सर, अभी गया है, सेंक्शन होगा । अभी हो रहा है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो पुराने सर्वे हुए थे उसमें लगभग 18 हजार सड़कें सर्वे ऐप में थी । सरकार ने यह निर्णय किया है कि 9 हजार सड़कें इस वित्तीय वर्ष में बनायेंगे और 9 हजार अगले वर्ष में बनायेंगे । इस वित्तीय वर्ष में जो सड़कें सर्वे में ली गयी है निश्चित रूप से आपके यहां भी ज्यादा है लेकिन हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आपके विधान सभा में 57 पथ को इस वित्तीय वर्ष में सेंक्शन किया गया है और 12 पुल आपके विधान सभा में सेंक्शन किये गये हैं । इसलिए इसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो बचा हुआ है उसको अगले वित्तीय वर्ष में कर देंगे ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे यहां के प्रभारी मंत्री भी है इसलिए हमारा हक है ।

अध्यक्ष : इसीलिए तो मंत्री जी इतना दे दिये हैं । फिर क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी कहे हैं कि ये सड़क प्राथमिकता के आधार पर। मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अवशेष योजना में 9 योजना चयनित की गयी है, प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गयी हुई है । हम मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि ये दो सड़क इसी वित्तीय वर्ष में करा ली जाए, हमारा विशेष आग्रह है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–178 (श्री कुमार सर्वजीत, बोधगया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन बसावट दादपुर अंसार नगर (चौधरी टोला) को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विभाग मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे करा लिया गया है जिसका सर्वे आई0डी0–82068 है । समीक्षोपरांत प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृति प्रदान कर पथ निर्माण करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, उत्तर प्राप्त है ।

तारांकित प्रश्न सं0–179 (श्री मोहम्मद अनजार नईमी)

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । 10:30 बजे तक उत्तर प्रकाशित नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयकांत पथ का 1.03 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–3 से ली गयी है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है । शेष बचे 2.02 किलोमीटर पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से दिनांक–15.11.2024 को बाहर हुआ है, जिसके कारण गत वर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अंतर्गत चयन नहीं हो सका है । अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अंतर्गत चयन कर निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता पर ले लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : हो जाएगा ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, हम कहना चाह रहे थे कि कोई भी हमारे यहां जितनी रोड बन रही है वह मेनटेनेंस पीरियड में है । मैंने तो सिर्फ एक ही रोड का उदाहरण दिया लेकिन किसी भी रोड का मेनटेनेंस नहीं हो पा रहा है। अब चूंकि विभाग को सूचित करने के बाद भी मेनटेन नहीं करता है जितनी सारी रोड है उसका टेन्योर ।

अध्यक्ष : आपने एक सड़क के बारे में पूछा उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है । इसलिए अब बैठ जाइये । प्रश्न में एक ही सड़क का नाम है ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0–180 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मनिहारी)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का सर्वे मोबाईल ऐप के माध्यम से छूटे हुए बसावट के तहत एकल सम्पकर्ता प्रदान करने हेतु करा लिया गया है । जिसका सर्वे आई.डी.– 22810 है। स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये, मनोहर बाबू ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोड की स्वीकृति की बात उत्तर में कही गयी है लेकिन स्वीकृति कब होगी और यह रोड कब बनेगा यही हम जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, स्वीकृति कब होगी ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, यह भी सेम प्रोसेस की है । हमारा जो एकल सम्पर्कता की सड़क है उसके लिए है । हम कह रहे हैं हमारे सर्वे में 18 हजार सड़कें हैं। इस वर्ष हम 9 हजार सड़क ले रहे हैं, इसका सर्वे आई0डी0 बना हुआ है। हम कुछ सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में ले रहे हैं और हो सकता है कि यह भी प्राथमिकता में हो । लेकिन अभी हम एश्योर नहीं हैं इसलिए कि लिस्ट नहीं बनी है क्योंकि 18 हजार सड़कों का हमें आईडिया थोड़ी होगा । अगली बार ले लेंगे, इस वित्तीय वर्ष में कुछ सड़कें होंगी और कुछ सड़कें अगले वित्तीय वर्ष में होंगी । सरकार का प्रयास है कि चुनाव से पहले करा लिया जाए और मनोहर जी को हम ऐसे बता देते हैं कुल 94 पथ इस वित्तीय वर्ष में इनके यहां लिया गया है, 324 करोड़ रुपये का इनके यहां सेंक्शन किया गया है ।

अध्यक्ष : पहले से ही सब बतला दिये थे क्या मनोहर बाबू ? सब करा ही लिया है, अब क्या है ?

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 हजार सड़कों में ये रोड है या नहीं ?

अध्यक्ष : अब हो गया । हो जाएगा, बैठिये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–181 (श्री शमीम अहमद, नरकटिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरिया प्रखंड के ग्राम कपरसंडी, मोगलिसपुर मध्य विद्यालय, सिसवनिया, सिसवनिया गोवरी सड़क, महम्मदपुर सिकरहना नदी के दायें किनारे पर अवस्थित है एवं जटवा कब्रिस्तान, जटवा–जनेरवा सड़क, सुन्दरपुर मस्जिद सुन्दरपुर पकड़िया टोला, जनेरवा पश्चिम हरिजन टोला तथा खैरी गांव सिकरहना नदी के बायें किनारे पर अवस्थित है ।

बाढ़ अवधि में नदी के जलश्राव में वृद्धि होने पर प्रश्नगत् ग्रामों के निचले ईलाकों में पानी का फैलाव होता है, परन्तु इससे कहीं कटाव नहीं हुआ है ।

जलश्राव घटने के क्रम में प्रश्नगत् ग्रामों के समीप नदी तट का आंशिक क्षरण हुआ है ।

बाढ़ अवधि 2024 में प्रश्नगत जटवा–जनेरवा सड़क, जो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित है का कटाव परिलक्षित हुआ, जिसे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित कर लिया गया।

वर्तमान में सभी प्रश्नगत् स्थल सुरक्षित है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है । हमारा पूरक यह है कि जब बाढ़ आती है तो यहां सिकरहना नदी से जितने गांव हैं ये लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर सब गांव है । कपरसंडी, मोखलिशपुर, सिसवनिया, गोबरी, जटवा कब्रिस्तान ये सारे गांव आधे किलोमीटर की रेंज में है । जब बाढ़ आती है तो चारों–तरफ पानी फैल जाता है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, बेडवार नहीं बनने की वजह से दहशत बनी रहती है । इस साल भी कटाव होने की वजह से जटवा–जनरेवा पथ बंद हो गया । फ्लड फाइटिंग के माध्यम से उसपर काम हुआ और चालू हुआ ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । आप पूरक पूछ ही नहीं रहे हैं ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, इस पर जल्द से जल्द बन जाए । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जो मैंने दिया है इस पर बेडवार बन जाने से परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो खुद कहा है कि वह जो सड़क हैं जटवा–जनरेवा । उसमें जो क्षरण हुआ, कटाव हुआ था उसको तो पिछले वर्ष हम ठीक रखे ही थे । आप कह रहे हैं स्थायी समाधान का । पानी का आना–जाना तो लगा रहता है । दूसरा वहां पर कोई कटाव नहीं क्षरण होता है, नदी किनारे का निचला इलाका है तो पानी बढ़ता है तो निचले इलाके में पानी फैलता है और जब पानी की वापसी होती है तो वह क्षरण कर वाशिंग–अवे हो जाता है और कुछ मिट्टी का ऊपर वाला स्तर पानी के साथ बहता है लेकिन हमलोग जो सड़क कह रहे हैं उसकी तो हिफाजत हमलोगों ने की थी और आगे भी उस सड़क पर यातायात, आवागमन बरकरार रहे । इसका सरकार या हमारा विभाग पूरा ख्याल रखेगा और उसको किसी हाल में कटने नहीं देगा ।

श्री शमीम अहमद : कई जगह से...

अध्यक्ष : अब हो गया, अब इसके बाद क्या पूछियेगा । दूसरे को मौका दे दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–182 (श्री फते बहादुर सिंह, डेहरी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि–

रोहतास जिलान्तर्गत सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 24.30 पर ग्राम देवरिया के पास पुल अवस्थित नहीं है, बल्कि नहर के वि०दू० 23.00 पर एकपथीय पुल निर्मित है, जो काफी पुराना एवं जर्जर स्थिति में है ।

प्रश्नाधीन एकपथीय पुल के स्थान पर द्विपथीय पुल के निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन तैयार होने के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है डेहरी प्रखंड का देवरिया ग्राम के उच्चस्तरीय नहर पर पुल बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और प्राक्कलन तैयार करने के बाद पुल बनाने का काम किया जाएगा । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने दिन में प्राक्कलन बनाकर के पुल बनाने का काम लग जाएगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो इनकी बात को सही माना है कि वह पुल जर्जर है और हम उस एकपथीय को द्विपथीय भी बनायेंगे । अभी प्राक्कलन तैयार करा रहे हैं और उसकी स्वीकृति के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण हो जाएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–183 (श्री अशोक कुमार चौधरी, सकरा)

(लिखित उत्तर)

श्री नितीन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कांटी प्रखण्ड के बैरिया गोलम्बर से पुरानी मोतिहारी रोड तक पथ में लगभग 1.00 कि0मी0 में पथ के दोनों ओर नाला निर्मित है ।

उक्त पथ के अवशेष 1.00 कि0मी0 लम्बाई में पथ के दोनों तरफ नाला निर्माण कर एवं बैरिया गोलम्बर के पास क्रॉस ड्रेन बनाकर इस नाले को

मुजफ्फरपुर–स्मार्ट सिटी द्वारा नव निर्मित नाले में मिला देने से इस स्थान पर जल जमाव की समस्या का समाधान हो जायेगा ।

संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री अशोक कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखण्ड के अंतर्गत नाला का निर्माण जो होना है, उसमें आधा नाला बनकर तैयार है और आधा नाला बचा हुआ है । उस नाला का निर्माण कबतक हो जाएगा, इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं ।

श्री नितीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस नाले की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी है । अगले वित्तीय वर्ष में इसको हमलोग करा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–184 (श्री रामबली सिंह यादव, घोसी)

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, पूछता हूँ, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । रामबली सिंह जी का उत्तर पढ़ दीजिए।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन पथ रूपा–बिगहा से डिहूरी गांव तक की कुल लम्बाई 1.60 किलोमीटर है, उक्त पथ का निर्माण पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा किया गया है । उक्त पथ की मरम्मती हेतु सर्वे कराया जा रहा है । ग्रामीण पथ सृदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करा लिया जाएगा ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, क्या इसी वित्तीय वर्ष में यह निर्माण कार्य हो जाएगा ?

श्री अशोक कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रयास होगा कि इसी वित्तीय वर्ष में ले लें लेकिन हम जानकारी के लिए माननीय सदस्य को कहना चाहेंगे पिछले दो वित्तीय वर्ष में आपके विधान सभा में कुल 76 पथ 128.436 किलोमीटर एवं एक पुल का निर्माण सरकार करा रही है जिसकी कुल लागत 88.26 किलोमीटर है । जब आपलोग सरकार को छोड़े थे, इसमें आप जिस पार्टी में है।

अध्यक्ष : 88 करोड़ या 88 किलोमीटर ?

श्री अशोक कुमार चौधरी : महोदय, कुल लागत 88.26 करोड़ है । 128.436 किलोमीटर सड़क बनायी गयी है और जब आपकी सरकार थी और माननीय नेता आये थे तो इस प्रदेश में मात्र 8 हजार किलोमीटर सड़क थी और आज 1 लाख 17

हजार किलोमीटर सड़क है । आपलोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए, माननीय नेता को धन्यवाद दीजिए । आपलोग अभिभाषण में इतनी बड़ी–बड़ी बात करते थे । धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता ने ग्रामीण सुदृढ़ीकरण के लिए इतनी बड़ी योजना लाकर के काम किया और यह नहीं कि कोई एन0डी0ए0 हैं, कोई आर0जे0डी0 हैं हरेक विधान सभा में सरकार ने काम कराने का काम किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

टर्न–4 / अभिनीत / 05.03.2025

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़कें हैं निश्चित रूप से, लेकिन ये सड़कें सुदृढ़ीकरण और मरम्मतीकरण की हैं । ये जर्जर सड़कें थीं । पहले की बनी हुई सड़क हैं लेकिन बावजूद, मरम्मत कराने के लिए सरकार ने 76 सड़कों की स्वीकृति दी है जरूर, हम माननीय मंत्रीजी को बधाई देंगे लेकिन यह सड़क 20 वर्ष पहले की बनी हुई है और इस 20 वर्ष में ये जो सड़कें खराब हुई हैं, चुनाव का वर्ष है तो अच्छी बात है हम बधाई देना चाहते हैं और जिस सड़क की चर्चा हमने की है वह उन तमाम सड़कों में सबसे खराब सड़क है । इसलिए हम माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि, जितनी सड़कें दिये हैं उसमें सबसे खराब सड़क यही है जिसे छोड़ दिया गया है ।

अध्यक्ष : कह तो रहे हैं कि करायेंगे ।

श्री रामबली सिंह यादव : हम माननीय मंत्रीजी से जानना चाहेंगे कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इस सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं 20 साल, डेढ़ साल तक आपके नेता प्रतिपक्ष इस विभाग के मंत्री थे लेकिन योजना नहीं लायें, वह आपकी चिंता नहीं किये, अब माननीय नेता लोक सभा चुनाव के बाद आपकी भी चिंता किये और इसी वित्तीय वर्ष में इनका भी रोड बना देंगे ।

अध्यक्ष : चलिए, बना देंगे ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–185 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह कि प्रश्न दो स्थान पर पुल निर्माण से संबंधित है। संदर्भित दोनों स्थल यथा–1. नवीनगर प्रखंड में पुनपुन नदी के ऊपर बड़वान गाँव के समीप एवं 2. बारूण प्रखण्ड में मुंसी बिगहा में बटाने नदी पर पुल निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत जिला संचालन समिति, औरंगाबाद द्वारा नवीनगर विधान सभा अंतर्गत अनुशंसित योजनाओं की प्राथमिकता सूची में क्रमशः क्रमांक–01 एवं 06 पर शामिल है। प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करा दिया जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरक पूछिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांत रहिए, शांत रहिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है । मैं माननीय मंत्रीजी से केवल यह जानना चाहता हूं कि दोनों मेरा जो पुल है, यह जो पुनपुन नदी पर बड़वान गांव के समीप में और बारूण प्रखंड के मुन्सी बिगहा में बटाने नदी पर जो पुल बनाना है बस इसका इंर्पोटेंश हम केवल बता देना चाहते हैं क्योंकि बारूण से जमहोर स्टेशन को जोड़ने वाला...

अध्यक्ष : विजय जी, पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, पूरक ही है । बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जमहोर स्टेशन को यह जोड़ता है और आर0ई0ओ0 का रोड है जिस पर पुल नहीं है और उस रोड का यूटिलिटी नहीं आ पा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : उसमें पुल निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा चुनाव के बाद माननीय नेता को एहसास हुआ कि बहुत जगहों पर पुल के लिए वोटों का बहिष्कार हुआ है । 9 साल के बाद पुनः माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना

की शुरूआत की और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो योजना जिला संचालन समिति के माध्यम से पुलों के लिए प्राथमिकताएं आयेंगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हरेक जिले से इतने ज्यादा पुल आ गये उतना सरकार के पास पैसा नहीं है । इस साल हमलोगों ने 600 पुल बनाने का निर्णय किया और अगले वित्तीय वर्ष में 400 पुल बनाने का निर्णय लिया है । माननीय सदस्य जो हैं इनका क्रमांक–01 एवं 06 पर प्राथमिकता सूची में यह पुल शामिल है । हमलोग ले रहे हैं और हमलोग विशेष ध्यान देंगे लेकिन फिर भी इनको हम जानकारी देते हैं कि पिछले दो वित्तीय वर्ष में कुल 126 पथ इनके विधान सभा में सरकार ने पास किया है जिसकी लंबाई 194.499 किलोमीटर है और दो पुल जिसकी लागत 188.30 करोड़ रुपये है, इसलिए माननीय नेता को धन्यवाद दीजिए और अपने नेता प्रतिपक्ष को बताइये कि जो भाषण में लंबी–लंबी बात बोल रहे थे, सरकार कैसे काम कर रही है ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय मंत्री जी..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया । अब बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य श्री दिलीप राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या–186 (श्री दिलीप राय, सुरसंड)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–187 (श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, रक्सौल)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रक्सौल प्रखंड के गम्हरिया नहर चौक से पुरन्दरा SSB कैम्प तक पथ का आरेखन त्रिवेणी बांध केनाल का है, जो जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में है। इस पथ की लम्बाई 9.70 कि0मी0 है। इस पथ के आरेखन में पड़ने वाली बसावट गम्हरिया चौक को NH-28A पथ से, मसना डीह टोला को हरनाही से पनटोका पथ से, चैनपुर को चैनपुर से गोनाहा पथ से, शीतलपुर एवं खिरलिचिया को शीतलपुर से खिरलिचिया पथ से, कौआडांगर को सिसवा से गाद बहुअरी से एवं पुरन्दरा SSB Camp को भेलाही RWD पथ से नेटुआ टोला तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है।

पथ के आरेखन में पड़ने वाले सभी बसावटों को एकल सम्पर्कता प्राप्त है। अतः प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रमोद जी, पूरक पूछिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, जवाब आया है लेकिन जवाब वहां के कनीय अभियंता और सहायक अभियंता इतना गलत–सलत जवाब दिये हैं बैठे–बैठे, मैं जब भी फोन करता हूं एस0डी0ओ0 को तो कहते हैं पटना मीटिंग में..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : हमने सर, जो सवाल किया था वह एस0एस0बी0 सीमांचल एरिया है और वह रोड लिंक रोड है जो आकर एन0एच0–28 से जुड़ेगा । इसमें गांव के गांव जोड़ दिये गये हैं बैठे–बैठे..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए । पूरक क्या है आपका ?

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : पूरक मेरा यह सवाल है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस रोड को फिर से कार्यपालक अभियंता से जांच करवाकर इस रोड को अतिशीघ्र बनवायें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, हमारी सरकार की योजना है कि पहले वैसी सड़कें जहां एकल संपर्कता नहीं है उसको प्राथमिकता देंगे और ये जिस बसावट की बात कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी एकल संपर्कता प्राप्त है । अगर..

(व्यवधान)

बैठिए न । बैठिए न, जवाब दे रहे हैं । इसमें कहा गया है कि वहां उस बसावट में एकल संपर्कता प्राप्त है । आपने कहा है उसको बनाने के लिए, अगर उसमें एकल संपर्कता प्राप्त नहीं होगी, सड़क का निर्माण नहीं कराया गया होगा तो इसी वित्तीय वर्ष में इसको बना देंगे । यदि एकल संपर्कता प्राप्त होगी तो इसमें दिक्कत होगी ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : सर, एस0एस0बी0 कितना इंपोर्टेंट चीज है और एन0एच0– 28 से जुड़ेगा । 10 किलोमीटर सड़क है वहां पर..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री राजेश कुमार । श्री शकील अहमद खाँ जी का राजेश जी पूछिए आप ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–188 (श्री शकील अहमद खाँ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ''राजा दिग्घी से रेलवे स्टेशन डण्डखोरा तक '' जाने वाली सड़क का निर्माण स्थानीय निकाय द्वारा कराया गया था। यह पथ जर्जर अवस्था में है। इस पथ को ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वित्तीय वर्ष में सम्मिलित कर पथ के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार, पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरक यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है । इसको इसी वित्तीय वर्ष में करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : इसका स्पष्ट जवाब दिये हैं कि प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में सम्मिलित कर पथ के निर्माण हेतु आगे कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सदस्य श्रीमती गायत्री देवी । बोलिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–189 (श्रीमती गायत्री देवी, परिहार)</u>

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग गायत्री देवी जी के प्रश्न का उत्तर पढ़ दीजिए। आपके पास स्थानांतरित होकर गया है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अगली बार जवाब दे देंगे सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जवाब अगली बार मिलेगा ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–190 (श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलांतर्गत बिस्फी विधान सभा क्षेत्र के सिमरी पंचायत के दुबियाही गांव के पास लगभग 500 हेक्टेयर में जल–जमाव रहता है ।

दरभंगा प्रमंडल हेतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना के तहत दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत जल–जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी में सुधार एवं विकास हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी के माध्यम से करया जा रहा है, जिसमें प्रश्नगत स्थल शामिल है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, दरभंगा प्रमंडल को भेजा गया है इसका प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, क्योंकि लालू जी की सरकार ने, उससे पहले पूरा विस्फी डूबा रहता था, अभी इतना ही डूबा हुआ है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कबतक इसको करवा देंगे ? बस इतना ही चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर में तो हमने स्पष्ट कहा है, इन्होंने जो समस्या बतायी है हमने उससे इक्तेफाक रखा है कि समस्या है लेकिन ड्रेनेज के मामले में जहां जिस जगह जल–जमाव रहता है उसका बेड लेवल देखकर फिर वह पानी ड्रेन होकर कहां जायेगा और फिर उसका अल्टीमेट ड्रेन कहां होगा यह सारा टोपोग्राफिकल सर्वे कराकर, फिर नदी का बेड लेवल, उस वाटर बॉडी का बेड लेवल, फिर रेन फॉल का डेटा जिस नदी से गुजरेगा वह सब लेना पड़ता है इसीलिए सबों कि समेकित योजना बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि तत्काल कुछ किया जाय, सरकार की लागत भी उस पर खर्च हो जाये और वह प्रभावी भी नहीं हो, इसीलिए हमने यह डीटेल, विभाग ने निर्णय लिया है और इसमें आपका यह जो सिमरी है विस्फी प्रखंड का उसके भी जल निकासी के संबंध में, इस स्टडी में शामिल करने का हमने निदेश दे दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–191 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत प्र नगत 213 योजनाओं में 112 को पूर्ण कर लिया गया है। भोश 101 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। सभी योजनाओं को जून–2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए अमरेन्द्र बाबू ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, जो जवाब है वह अधूरा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री पूरा करें । मेरा यही पूरक है इसमें और यह बताते हुए कि यह

योजना 2024–25 तक ही है और यह पूरा करना है । जल–जीवन–हरियाली से संबंधित है । शहरी योजना है ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि जून 2025 तक पूरा करेंगे । जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, यह मार्च तो चल रहा है न, इसी 31 मार्च तक करना है, कैसे पूरा करेंगे ? एक और दूसरी बात है महोदय, ये योजना उन्हीं क्षेत्रों में लागू होनी थी जहां सिंचाई के लिए किसानों को बड़ी सुविधा प्राप्त नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है । उन्होंने इसका जो प्रारंभ किया था तो उन्हीं इलाकों के लिए किया था जिन इलाकों में किसानों को सिंचाई हेतु जो बड़ी सुविधा थी...

अध्यक्ष : अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : आहर है, पईन है, तालाब है, पोखर है उन सबका जीर्णोद्धार कराना भी था । महोदय, उससे जुड़ी हुई एक और बात है सरकार ने उस पर ध्यान दिया है लेकिन और ध्यान देने की जरूरत है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो आहर, पईन, पोखर, जिनका अतिक्रमण हो चुका है, अतिक्रमणकारियों ने उनका दखल कर लिया है, उनको नष्ट कर दिया है, क्या उनको भी पुनर्जीवित करने का विचार रखते हैं ?

टर्न–5 / हेमन्त / 05.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट है । माननीय सदस्य ने जो बात कही थी कि कब तक पूरा करेंगे ? उत्तर में स्पष्ट दे दिया गया है कि जून, 2025 तक सारे कार्यों को विभाग के द्वारा पूरा कर लिया जायेगा । मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने जो जल जीवन हरियाली के विषय में सवाल किया था कि पिछले पांच साल, पिछले पांच साल में महोदय, 2318 स्कीम ली गयी हैं जिसमें से विभाग ने 2217 स्कीम को पूरा कर लिया है, जो शेष बची 213 थी उसमें से भी पूर्ण करके 101 अब बची हुई हैं जिसको जून, 2025 तक पूरा कर लिया जायेगा । जहां तक माननीय सदस्य का आग्रह था कि अतिक्रमण है, जहां भी अतिक्रमण होता है योजनाएं चयनित की जाती हैं, तो वहां संबंधित जिलाधिकारी से अतिक्रमण हटवाकर कार्य पूर्ण किया जाता है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सीधे क्या उनका डायरेक्शन होगा जिलाधिकारी को, बाकी को ऐसा करने के लिए । कहीं नहीं हो रहा है । इसलिए मैंने इस बात को यहां पर उठाया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, दिखवाइये इसको ।

तारांकित प्रश्न संख्या–192 (श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, गोपालपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–193 (श्री कुंदन कुमार, बेगूसराय)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ शीर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना ;डडळैन्ल्द्ध अंतर्गत बेगुसराय वीरपुर पी0डब्लू0डी0 रोड कोरिया पथ के नाम से स्वीकृत है जो निविदा की प्रक्रिया में है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 25.03.2025 है। निविदा निष्पादन उपरांत जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये कुंदन जी ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से कोरिया गांव तक की सड़क के बारे में था । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको शीघ्र बनवा देंगे । मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–194 (श्री बिजय सिंह, बरारी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये बिजय जी ।

श्री बिजय सिंह : महोदय, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्रश्नाधीन एस0एच0–77 के नरहैया से शरीरफगंज पथ की कुल लम्बाई 38.784 कि0मी0 है । इसमें से जल जमाव से प्रभावित स्थल स्थानों सहित कुल 7.328 कि0मी0 के नवनिर्माण हेतु संसाधन की उपलब्धता एवं तकनीकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि शरीफगंज से नरहैया जाने वाली सड़क एक मुख्य सड़क है, जो प्रखंड को जोड़ती है, 7 कि0मी0 नहीं बनने के कारण, 56 कि0मी0 के रोड में 7 कि0मी0 रोड नहीं बन पाया और वह सारा रोड टूटकर जीर्णशीर्ण अवस्था में है जिसके कारण यह जलजमाव हो रहा है, तो इसकी तो प्राक्कलन राशि बनकर तैयार है, दो वर्ष हो गये हैं अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है ? माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कब वह बनकर तैयार होगा ? जब पुनरीक्षण हो चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, अभी जो इसकी तकनीकी रिपोर्ट आयी है उसमें यह है कि नाला निर्माण की बात है । माननीय विधायक जी ने इसमें जो प्रश्न किया है वह है सड़क निर्माण का, लेकिन हमने इसका तकनीकी मंगाया है और अगले वित्तीय वर्ष, चूंकि इस योजना का प्राक्कलन आया हुआ है, अगले वित्तीय वर्ष में इसको ले लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–196 (श्री संजीव कुमार, परबत्ता)

अध्यक्ष : संजीव जी, पूरक पूछिये ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर यही है कि इनका कहना सही है कि एक और अतिरिक्त स्लूईस गेट की वहां पर आवश्यकता है । हम लोगों ने योजना तैयार कर ली है और अगले वित्तीय वर्ष में उसका निर्माण कार्य करा लिया जायेगा ।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है, स्लूईस गेट का निर्माण करा दिया जाय।

अध्यक्ष : उन्होंने कहां कहा कि महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री संजीव कुमार : अगले वित्तीय वर्ष बोल रहे हैं । इस बार करवा देते तो अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : आप बताइये कि आज क्या तारीख है ?

श्री संजीव कुमार : सर, जितना जल्दी हो, हो जाता । यह आग्रह है मेरा ।

अध्यक्ष : यह ठीक है आपका कि जल्दी हो जाय ।

श्री संजीव कुमार : तीन चार पंचायत के लोग प्रभावित हैं, देवठा पैंकात के लोग प्रभावित हैं । हजारों एकड़ जमीन डूबी रहती है, किसान लोगों को राहत मिलेगी ।

अध्यक्ष : जितना जल्दी हो सके करवायेंगे ।

श्री संजीव कुमार : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–197 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, पिपरा, पूर्वी चम्पारण)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–198 (श्री अजय कुमार सिंह, जमालपुर, मुंगेर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि:–

मुंगेर जिला के धरहरा प्रखण्ड में अवस्थित सतघरवा जलाशय में झरने का पानी लाने हेतु पहाड़ी के तलहटी से जलाशय तक नाली निर्माण कार्य की योजना की स्वीकृति माह मार्च, 2023 में प्रदान की गयी थी।

प्रश्नगत योजना का कार्य स्थल वन भूमि क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण इस योजना के कार्यान्वयन निमित वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर योजना का कार्यान्वयन करा लिया जायेगा। मुख्यालय के द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये अजय जी ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है उसमें विभाग की ओर से कहा गया है कि वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर योजना चालू की जायेगी, लेकिन वर्ष 2023 में दिसम्बर माह तक वन विभाग ने अनापत्ति दी थी । उस अनापत्ति की पीरियड में इस योजना का निर्माण क्यों नहीं हो पाया ? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि अनापत्ति इसने दी, तो पीरियड क्या है ? देकर वापस ले ली क्या ? हम कह रहे हैं कि अनापत्ति के लिए तो हम मांग रहे हैं

। अनापत्ति अगर दे दे, अगर दी है, तो आज दे दीजिए हम कल से काम शुरू करा देंगे ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस अनापत्ति की बात की, 2023 में दो योजनाओं के लिए अनापत्ति दी गयी थी, एक कालीघाटी योजना और एक इसके लिए और फॉरेस्ट विभाग ने यह तय किया था कि आप 31 दिसम्बर, 2023 तक इस योजना को पूर्ण कर लीजिए । तो उसमें कालीघाटी योजना पूर्ण हो गयी और इस योजना में झमेला यह हो गया कि पहाड़ से ही गिट्टी फोड़कर संवेदक लगाना चाहता था, तो जाहिर सी बात है कि इसको फॉरेस्ट रोक देगा । यह संवेदक और विभाग की लापरवाही के चलते अनापत्ति पीरियड में योजना पूर्ण नहीं हुई, मैं यह कहना चाहता हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह संवेदक और स्थानीय लोगों के बीच की बात तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी समीक्षा हम अपने स्तर पर कर लेंगे और वन विभाग से भी सम्पर्क करके, क्योंकि अच्छी योजना है, विभाग तो चाह ही रहा है, हम कुछ उपाय करने की कोशिश करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–199 (श्री अवध विहारी चौधरी, सिवान)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि भवन प्रमंडल, सीवान द्वारा भवन निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल अंतर्गत आने वाले भवनों का ही मरम्मति कार्य कराया जाता है।

2. अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि भवन निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल अंतर्गत आने वाले भवनों में कराये गये मरम्मति कार्य की तकनीकी जाँच के उपरांत ही नियमानुसार संवेदकों को भुगतान किया जाता है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये अवध विहारी बाबू ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैं पूछता हूं और जो सरकार के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ है उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं । मेरे प्रश्न करने का मकसद यही है कि सरकार मरम्मति, विशेष मरम्मति के लिए जो भवन निर्माण विभाग कुर्सी क्षेत्र एरिया है उसके लिए पैसा देता है । यह पैसे प्रतिवर्ष दिये जाते हैं, परंतु जो विभाग के द्वारा कार्य कराये जाते हैं भवन के, मरम्मति या विशेष मरम्मति वह मजबूती के साथ नहीं, बल्कि मेरे देखने से वह लीपापोती जैसा काम होता है ।

मेरे प्रश्न करने का मकसद यही है कि सरकार उसको गंभीरता से देखे और देखकर कार्य सही तरीके से प्राक्कलन के मुताबिक हो । इसी के लिए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और जो प्रतिवेदन आये हैं, वह सभी स्वीकारात्मक नहीं अस्वीकारात्मक हैं । तो भवन की मरम्मति में गड़बड़ी की शिकायत मैं करता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को । मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करावें । मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं । मेरा क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि पैसे का बंदरबांट कर लिया जाता है और कार्य जो होना चाहिए वह न के बराबर होता है । मैं चाहूंगा कि क्या मंत्री स्वयं इसकी अपने स्तर से जांच कराकर कार्यों में गुणवत्ता हो, इस दिशा में आप कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिया गया है और नियमानुकूल भुगतान भी होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक मामला अगर माननीय सदस्य का है, सदस्य काफी सीनियर सदस्य हैं, तो आपका कोई स्पेसिफिक मामला अगर होगा, आप बता दीजिएगा, तो उसको हम लोग विभागीय स्तर से उच्चस्तरीय जांच करवा लेंगे । कोई अगर होगा, तो आप लिखकर भी दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा, तो हम लोग जांच उसकी निश्चित रूप से करवा लेंगे ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, आपके माध्यम से मैं विभागीय मंत्री से यही कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न आये हुए हैं, प्रश्न के जो जवाब आये हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और कहना चाहता हूं कि क्या आप पुनः अपने स्तर से जांच करा लेंगे और गड़बड़ी पायी जायेगी, तो इसमें जो संलिप्त दोषी होंगे उनके ऊपर सक्षम कार्रवाई करेंगे ?

टर्न–6 / धिरेन्द्र / 05.03.2025

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें कोई गड़बड़ी करने वाले बचने वाले नहीं हैं । अगर गड़बड़ी करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो हम अपने स्तर से, अपने विभागीय उच्च अधिकारियों से जाँच करवा लेंगे, हमने कहा है कि आप स्पेसिफिक मामला हमें बता दीजियेगा, उसकी जाँच हमलोग करवा लेंगे, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उस अधिकारी के ऊपर जरूर कार्रवाई की जायेगी और कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–200 (श्री अजीत शर्मा, भागलपुर)

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है । आपके पास हार्ड कॉपी आया होगा, नेवा पर अपलोड नहीं है । माननीय मंत्री जी अगर जवाब दे दें तो बढ़िया होगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग । कृषि विभाग में ट्रांसफर हुआ है, अगली बार जवाब दिया जायेगा ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, कृषि विभाग का है, इसमें एजेंसी पुल निगम है ।

श्री अजीत शर्मा : अगले डेट में बता दिया जाय ।

अध्यक्ष : अगले डेट में बता दिया जायेगा । अभी ट्रांसफर होकर गया ही है ।

(व्यवधान)

आप मंत्री नहीं बने हैं न, इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही है, बन जाते तो समझ में आ जाता कि ट्रांसफर होने के बाद क्या दिक्कत होती है । श्री अवध विहारी बाबू यह बात नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि क्या होता है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, जल्द उत्तर दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : अगली बार जवाब आयेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–201 (श्री विनय कुमार, गुरुआ)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग । यह प्रश्न ट्रांसफर होकर गया है पंचायती राज विभाग में ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, अगले डेट में जवाब देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, अगली बार जवाब देंगे ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अगले हफ्ते जवाब आयेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–202 (श्री छत्रपति यादव, खगड़िया)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में उल्लेखित ग्राम वरखंडी टोला को मथार से वरखंडी टोला मुख्यमंत्री ग्राम सर्म्पक योजना अन्तर्गत पथ के द्वारा एकल सम्पर्कता प्राप्त है एवं चम्मन टोला ग्राम को बलीया कार्य प्रमण्डल द्वारा मुंगेर–खगड़िया पथ से रामदेव हाउस से मुंगेर घाट तक पथ द्वारा संपर्कता प्राप्त है।

वरखंडी टोला से चमन टोला के बीच कोई योग्य बसावट नहीं होने के कारण यह विभाग के किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है। अतः इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : छत्रपति जी, पूरक पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न का जवाब आया है, यह सही जवाब नहीं है, संतोषजनक नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री छत्रपति यादव : महोदय, हमने प्रश्न किया है कि प्रधानमंत्री सड़क वरखंडी टोला से चम्मन टोला होते हुए मुंगेर पथ को जोड़ने वाली सड़क, यह दियरा क्षेत्र है रहिमपुर दक्षिणी पंचायत, मध्य पंचायत, उत्तरी पंचायत को जोड़ने का एक मात्र विकल्प सड़क यह है । बार–बार विभाग उत्तर देता है कि योग्य बसावट नहीं होने के कारण यह सड़क नहीं बन सकती है । मात्र 01–01.25 किलोमीटर यह सड़क है, यह बनने से पूरा दियरा क्षेत्र का बाईपास का सड़क होगा, सरकार का पैसा वेस्ट नहीं होगा ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, हम मंत्री जी से चाहते हैं कि सड़क का निर्माण विभागीय स्तर पर कैसे होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो जवाब आया है, इसमें है कि बसावट नहीं होने के कारण लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहाँ बसावट भी है और एक बाईपास का निर्माण वहां पर किया जा सकता है, इसके बनने से तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि सुलभ संपर्कता में वैसे जगह पर जहाँ पर प्रखंड और हेडक्वार्टर जाने के लिए, मुख्यालय जाने के लिए या अस्पताल हो, ब्लॉक हो तो उसमें हमलोग एक बाईपास का प्रावधान करने का माननीय नेता की नीयत है और उन्होंने उसके लिए पैसे का प्रावधान

किया है । हम इसकी जाँच करा लेते हैं अगर माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं वैसा होगा तो यह काम करा दिया जायेगा ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष जी....

अध्यक्ष : अब हो ही गया, अब क्या पूछियेगा ?

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं चूंकि ये जानते हैं....

अध्यक्ष : आप मंत्री जी से मिलकर बता दीजियेगा ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, सदन में ही बता देते हैं चूंकि सदन की बात है । लास्ट सदन है, चुनाव होने वाला है । महोदय, यह तीन साल से मांग कर रहे हैं, विभाग टाल–मटोल कर रही है, यह बाईपास नहीं है,

अध्यक्ष : इन्होंने जाँच कराने के लिए कहा ही है ।

श्री छत्रपति यादव : मुख्यमंत्री की सारी योजना को सफल बनाने के लिए यह सड़क है । यह बनने से वहां जितने भी दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसी का क्षेत्र है और वह मात्र 1.5 किलोमीटर सड़क नहीं होने से अस्पताल जाना, बाईपास पर जाना और बड़ी गाड़ी का आना–जाना बंद है ।

अध्यक्ष : छत्रपति जी, बैठ जाइये, हो गया ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, हम अनुरोध करते हैं कि इसको करा दिया जाय ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–203 (श्री चन्द्रहास चौपाल, सिंहेश्वर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–204 (श्री प्रेम शंकर प्रसाद, बैकुंठपुर)</u>

श्री नितिन नवीन, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रश्नगत मोहम्मदपुर करणकुदरिया (एस॰एच॰–90) है, जिसकी कुल लम्बाई 20.00 किलोमीटर एवं पथ परत की चौड़ाई 7.00 मीटर है । उक्त पथ का 19.75 किलोमीटर पथांश Bituminous एवं 0.25 किलोमीटर Cement Concrete Pavement है । वर्तमान में यह OPRMC Package No.-23A अन्तर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है । सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से IRC-67 के अनुरूप Sign Board एवं IRC-35 के मानक अनुरूप Road Marking एवं Rumble strip भी अध्ष्ठिापित किया गया है ।

संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रेम शंकर जी, पूरक पूछिये ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, पूरक यह है कि इन्होंने जो जवाब दिया है वह संतोषजनक नहीं है । मेरा प्रश्न था कि आखिर इस रोड में जब रोड का चौड़ीकरण कर सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण कर ली गई है और जमीन अधिग्रहण कर सारा पैसा भी जमीन वाले को दे दिया गया है तो टू लेन बनाने में क्या दिक्कत हो रही है ? आये दिन वहां घटना घटती है, महीना में कम–से–कम 15–20 घटनाएं उस रोड पर घटती है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उस रोड का चौड़ीकरण कब तक हो सकता है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, यह सड़क ओ॰पी॰आर॰एम॰सी॰ से संधारित है और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर इसको हमलोग चौड़ीकरण के लिए विचार कर रहे हैं, उसमें इस योजना को लेंगे।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : जी, धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–205 (श्री राकेश कुमार रौशन, इस्लामपुर, नालन्दा)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पैमार नदी पर अवस्थित मालीसाढ़ बराज से आत्मा गाँव तक नहर निर्मित है जिसके बायें बांध पर नहर सेवा पथ है । जैतीपुर गाँव जलवार नदी के दूसरी तरफ अवस्थित है ।

नहर सेवा पथ पर मालीसाढ़ के सिढ़ारी गाँव (आत्मा गाँव से 500 मीटर पूर्व) तक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बिटुमिनस सड़क निर्मित है ।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित सड़क से आवागमन सुगमतापूर्वक हो रहा है ।

वर्तमान में नहरों से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है तथा नहरों के पक्कीकरण करने एवं नहर के तटबंधों को चौड़ीकरण कर सड़क बनवाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : राकेश जी, पूरक पूछिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, सरकारी पदाधिकारी के द्वारा माननीय मंत्री जी को जो जवाब समर्पित किया गया है, उसमें सही वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया गया है । महोदय, यह जो पैमार नहर है वह माली साड़ से निकलकर कपश्या तक सीधे गयी है, उसके बाद कपश्या से यह नहर दो भाग में बंट जाती है एक नहर पूरव तरफ गयी है जो आत्मा तक जाती है और दूसरी नहर जो है वह सिढ़ारी गाँव से आगे तक गयी है । सिढ़ारी गाँव से आगे वाली नहर में संपर्कता पथ नहीं दिया गया है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पहला पूरक प्रश्न यह पूछना चाहूँगा कि छूटे हुए नहर पर क्या संपर्कता पथ का निर्माण क्या विभाग कराना चाहती है ? दूसरा मेरा पूरक प्रश्न इसी से संबंधित है पैमार सिंचाई योजना में माननीय मंत्री जी भी जैसा जानते हैं कि उन्नयन का काम चल रहा है और यह दो वर्षों से चल रहा है लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है जिससे सरकार का जो लक्ष्य है कि हर खेत को पानी तो वहाँ किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : तो सरकार कब तक इस कार्य को पूरा कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : आपका दो पूरक हुआ ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, एक और पूरक है, तीनों पूछ लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, तीनों एक ही बार पूछ लीजिये । तीसरा पूछिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, तीसरा पूरक यह है कि क्या सरकार, इन्होंने जवाब दिया है कि नहर के पक्कीकरण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अन्य जगहों पर नहर के पक्कीकरण की योजना किस आधार पर चलायी जा रही है ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जरूर कहा है कि यह योजना नहीं है । आपने प्रश्न में ही कहा है कि वह जो वितरणी है उसका बायां और दायां दोनों नहर का छोर, किनारा जो है तो बायें तरफ की सड़क का पक्कीकरण ग्रामीण कार्य विभाग अशोक जी के विभाग द्वारा निर्मित है और यह सड़क 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक जाती है और यह नहर का टेल इंड है, वहीं पर वह नहर वितरणी समाप्त हो जाती है और चूंकि एक तरफ से आवागमन बिल्कुल अच्छे सुचारू रूप से हो रही है और जहां तक जैतीपुर गाँव की बात आपने की है तो यह जो पैमार नदी पर रेयर है उससे नहर निकल

कर जाता है और जैतीपुर गाँव तो फिर दूसरी नदी जलवार नदी के उस तरफ है तो फिर अगर सड़क जायेगी तो फिर उस नदी को कैसे क्रॉस करेगी ।

इसलिए हमने कहा है, इसलिए नहीं कि हम बनाते नहीं हैं, ऐसा तो हमने कहा नहीं है कि हम नहीं बनाते हैं । अभी नहर के दोनों तरफ जो सड़क है उसमें बायीं ओर वाली सड़क ग्रामीण कार्य विभाग ने बना दिया है और आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है और चूंकि नहर के वितरणी के अंतिम छोर तक बना हुआ है इसलिए दायें–बायें में कोई फर्क नहीं है, जो लोग दायीं तरफ भी जाना चाहते हैं उधर से घूम कर चले जाते हैं और आगे फिर जलवार नदी है जिसके उस पार जैतीपुर गाँव है इसीलिए इसमें दिक्कत हो रही है और हम तो बनाये हैं और बना हुआ है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मेरा प्रश्न.....

अध्यक्ष : अब हो गया आपका तीन पूरक ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, एक मिनट, आप ही के सहूलियत के लिए एक बार में तीनों पूरक पूछा था ।

अध्यक्ष : आप तीन पूरक पूछ चुके । बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–206 (श्री अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई)</u>

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, हमें जो उत्तर मिला है उसमें जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित लिखा हुआ है ।

अध्यक्ष : हाँ, जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर हुआ है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग आज जवाब देंगे ?

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, बता दिया जाय, इसका उत्तर तो चाहिए ही ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, श्री अमरजीत कुशवाहा जी का जवाब देंगे ।

महोदय, प्रश्नगत सड़क हथुआ शाखा नहर के 27.44 किलोमीटर से 55.91 किलोमीटर तक नहर का सेवा पथ है, उक्त सेवा पथ के पक्कीकरण का कार्य वर्ष 2019 में कराया गया था लेकिन जिसमें एकरारनामा के तहत सड़क के रख–रखाव की अवधि भी मार्च, 2026 तक है निर्मित पथ के क्षतिग्रस्त भागों में संवेदक द्वारा रख–रखाव का कार्य कराया जा रहा है और इसमें, यह बात आपका कहना सही है कि रख–रखाव में संवेदक के द्वारा इस बीच में शिथिलता बरती गयी थी जिसके कारण उनको शो–कॉज नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रारंभ की जा रही है । वैसे जो संवेदक ने सड़क बनायी

है उसको इसका मेंटेनेंस मार्च, 2026 तक करना है । इसलिए वह कर रहा है, अभी जब विभाग का दवाब आया है, वह कर रहा है अगर फिर शिथिलता बरतता है तो उसको हमलोग काली सूची में भी डालने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अमरजीत जी । समय पूरा हो गया है ।

टर्न–7 / संगीता / 05.03.2025

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–207, श्री राम सिंह (बगहा)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि सियराहा (सिरहा) नाला में गाद जमा होने के कारण बरसात के दिनों में नाला का पानी सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता है। फलस्वरूप बरसात के दिनों में टेसरहिया–बथवड़ीया, बिबी बनकटवा, लगुनाहा–चौतरवा पंचायतों के आस–पास के खेतो में जल जमाव हो जाता है। बरसात के अलावा अन्य मौसम में जल जमाव की स्थिति नही रहती है।

सियराहा (सिरहा) नाला के गाद सफाई के उद्देश्य से योजना तैयार की जा रही है। प्राक्कलन तैयार होने के उपरान्त आगे की कार्रवाई की जायेगी।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, जल्दी पूछिए, समय हो गया ।

श्री राम सिंह : कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि 3–4 पंचायतों के 4 हजार एकड़ जमीन में जल जमाव होती है बरसात के दिनों में तो बरसात के दिनों में जल जमाव होगी तो खरीफ की खेती कैसे होगा...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री राम सिंह : वही पूछ रहा हूं महोदय कि सियराहा नाला का कब तक सफाई होगा कि खरीफ की खेती लोग करेंगे...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इनका हमने कहा है कि इसका जो कार्य योजना बनाकर स्वीकृति दे दी गई है अब अगले वित्तीय वर्ष में कार्य करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–05, मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

(व्यवधान)

बैठ जाइए ।

श्री महबूब आलम, स0वि0स0, श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0, श्री महानंद सिंह, स0वि0स0...

(व्यवधान)

आप क्या चाहते हैं, माले के लोगों की बात नहीं सुनी जाय...

(व्यवधान)

श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0, श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0, श्री सूर्यकान्त पासवान, स0वि0स0, श्री शमीम अहमद, स0वि0स0, श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0 एवं श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 ।

आज दिनांक–05, मार्च, 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–171(1) एवं नियम–47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सिवान जिला के......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शून्यकाल में बोल रहे हैं न...

(व्यवधान)

शून्यकाल में बोल रहे हैं न आप ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम तो आप ही की पार्टी के मेंबर को पढ़वा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा ?

(व्यवधान)

अब मैं क्या करूं, बताइए न, आप ही के पार्टी के मेंबर हैं, वो आपको नहीं बोलने देना चाहते हैं ।

श्री महबूब आलम : महोदय...

अध्यक्ष : आपकी पार्टी के मेंबर खड़े हैं, मैं कैसे बोलने दूं आपको, बोलिए ।

(व्यवधान)

आप पहले बैठिए, अपने स्थान पर जाइए । आप अपने स्थान पर जाइए पहले...

(व्यवधान)

पहले अपने स्थान पर जाइए । आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए पहले...

(व्यवधान)

अब चलिए आगे बढ़िए तब, छोड़ दीजिए । आप नहीं बात करना चाहते हैं, नहीं पढ़ने देंगे हम । अब आपके ही मेंबर रोक रहे हैं आपको, आप ही को रोक रहे हैं, मैं क्या करूं बताइए ।

(व्यवधान)

आप ही के मेंबर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं । लगता है कि वे नहीं चाहते हैं कि आप नेता रहिए, इसीलिए ये बीच–बीच में खड़े होकर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री महबूब आलम : महोदय...

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार में हाल के दिनों में दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाएं सरकार के तथाकथित सुशासन की पोल खोल रही है । मधुबनी में ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के नाम पर मौलाना

फिरोज की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई, जमुई में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश, बारसोई के सुधानी थाना प्रभारी द्वारा अजान पर अभद्र टिप्पणी, मुजफ्फरपुर में हिरासत में शिवम झा की निर्मम हत्या, बनारस में बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ दुष्कर्म और हत्या पर सरकार की आपराधिक चुप्पी, सिवान के दरौली प्रखंड के पचबेनिया गांव में भर जाति की दो बच्चियों के बलात्कारी व मुख्य आरोपी शाह माफिया बिहारी पांडे तथा उसके अन्य साथियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना, बेगूसराय में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, गया में भूमि विवाद के चलते संजय मांझी का हाथ काटना और मात्र एक सौ रुपये मजदूरी मांगने पर सज्जन मांझी की हत्या की घटनाएं स्पष्ट करती है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है यह केवल प्रशासन की विफलता नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में पल रहे सामंती आपराधिक तत्वों के बढ़ते दुस्साहस का प्रमाण है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जो लिखा हुआ है वह पढ़िए, लिखा हुआ पढ़िए ।

श्री महबूब आलम : अतः बिहार में बढ़ती साम्प्रदायिक हिंसा, दलितों और महिलाओं पर हो रहे बर्बर अत्याचारों के खिलाफ सदन का कार्य स्थगित कर बहस करने की मांग करते हैं।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

शून्यकाल

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड के कुम्हारटोली चुनीमारी पुल की मांग दशकों से लगातार उठती रही है नदी के दोनों छोड़ PMGSY सड़क है । पुल नहीं होने के कारण आवागमन ठप है । जनता निराश व आक्रोशित है ।

मैं जनहित में कुम्हारटोली चुनीमारी पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत असुरा–निशन्द्रा के बीच पुल का निर्माण असुरा गांव के निकट अवस्थित चचरी पुल के नजदीक से किया जाय ताकि ग्रामीणों को इस छोड़ से दूसरी छोड़ जाने में सहूलियत हो ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दर्शाए गए मार्ग में ही पुल का निर्माण कराया जाय ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज के पोठिया प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 50km दूरी तयकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है । जिससे छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः मैं डिग्री कॉलेज खोलवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर सभी जनवितरण प्रणाली दुकान के विक्रेता (डिलर) को अन्य राज्यों की तरह प्रतिमाह 20000/– बीस हजार रुपये माहवारी मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखण्ड से होकर गुजरने वाली कदहर नहर जो नवादा जिला से चलकर आई है । कई स्थानों पर नहर में सिल्ट जमा रहने से पानी का बहाव काफी धीमी हो गई है । किसानों को पटवन में कठिनाई होती है ।

अतः जीर्णोद्धार कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, विगत 17 वर्षों से पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नहीं होने के कारण बिहार के लाखों BLIS,MLIS के छात्र–छात्राएं इस क्षेत्र में रोजगार के लिए भटक रहे हैं । छात्र–छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र बहाली करने की कृपा करें ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा रूट कलर कोडिंग लागू करने से पहले तय रूटों पर ऑटो स्टैण्ड का निर्माण एवं ई–रिक्शा का चार्जिंग प्वाइंट नहीं होने से चालकों को कठिनाई होगी ।

मैं सरकार से रूट कलर कोडिंग से पहले ऑटो स्टैण्ड एवं चार्जिंग प्वाईंट बनवाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड शेरघाटी के ग्राम पंचायत–श्रीरामपुर में ग्राम–बी टी बिगहा महादलित टोला में केवाल मांझी के घर से गोरु मांझी के घर होते हुए अहरा तक पीसीसी नाला का निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से निवेदन करती हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा प्रखंड के जनसंख्या के घनत्व के आधार पर आमोदेई पंचायत के पांच पिछड़े वार्ड और रघुनाथपुर पंचायत के तीन पिछड़े वार्डों को समायोजित कर विकसित करने हेतु प्रस्तावित नए पंचायत रमण नगर की अतिशीघ्र स्थापना कराने की मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधान सभा अन्तर्गत बन रहे रोसड़ा– रामनगर दरभंगा एन0एच0 एवं पटना– पूर्णिया एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक परिक्षेत्र विकसित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

टर्न–08 / सुरज / 05.03.2025

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जान जोखिम में डालकर रात्रि प्रहरी विद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा करते हैं । उन्हें महज 5000 रु0 मानदेय दिया जाता है । सरकार से रात्रि प्रहरी की सेवा स्थायी करने एवं 20 हजार मानदेय देने की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, राज्य में गृह विभाग परिपत्र सं0–11287 दिनांक–20.12.1995 को पुर्नजीवित कर एवं विभागीय पत्रांक–12094 दिनांक–11.11. 2004 को निरस्त कर सेवानिवृत्त दफादार–चौकीदारों के आश्रितों को कुछ जिलों में नियुक्त किया गया है ।

मैं छूटे हुये शेष लगभग 5000 आश्रितों को रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंचल कार्यालयों में रिश्वतखोरी चरम पर है । एक तरफ दाखिल खारिज और परिमार्जन कराने के लिये लोगों के पैरों के जूते घिस जा रहे हैं । तो दूसरी तरफ भू–माफियाओं का गलत काम

रातों–रात हो रहा है । रिश्वतखोरी बंद कराने के लिये सरकार से मांग करता हूं ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरा प्रखंड में चुंआ चुनकातरी में सुखनर नदी पर पुल निर्माण से कागेसर और चुंआ पंचायत के लगभग 10 हजार लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और प्रखंड मुख्यालय तक आवागमन में 10 किलोमीटर की कटौती होगी । खैरा प्रखंड में चुंआ चुनकातरी में सुखनर नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में कार्यरत पैक्स प्रबंधकों का सेवा 60 वर्ष करने तथा 20,000 रुपया मानदेय निर्धारित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में वर्ष 2010 में महादलितों के विकास के लिये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रति पंचायतों के विकास मित्रों का चयन किया गया । यह एक बड़ा उपकार था । अब विकास मित्रों को अन्य सुविधाओं के साथ राज्यकर्मी का दर्जा की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद आपको सरकार की आपने प्रशंसा की । बैठिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखंड अंतर्गत पीपरा–परसाईन पंचायत के लालबन्दी ग्राम होकर बहने वाली हरदी नदी पर स्लुईस गेट नहीं होने से किसान को सिंचाई करने में कठिनाई होती है ।

अतः लालबन्दी ग्राम के हरदी नदी पर स्लुईस गेट का निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधानसभा के एन0एच0–57 से फारबीसगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय तक पहुंच पथ एवं उपकारा भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर नवनिर्मित फौजदारी कोर्ट के यथाशीघ्र शुभारम्भ व फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं के सुविधाओं हेतु स्थायी वकालतखाना भवन निर्माण कि मांग सदन से करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिला को जोड़ने वाली लालबकेया नदी पर मधु छपड़ा एवं जमुआ के बीच पुल निर्माण पूर्ण होने के बावजूद एप्रोच सड़क निर्माण नहीं होने से विगत 2 वर्षों से आवागमन बंद है ।

सरकार शीघ्र एप्रोच सड़क निर्माण कर पुल पर आवागमन शीघ्र चालू करावे ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत डंडारी प्रखंड के कटरमाला उत्तरी पंचायत भौगोलिक रूप से प्रखंड से अलग–थलग रहने के कारण आमलोगों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः कटरमाला उत्तरी पंचायत को नावकोठी प्रखंड में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

सुनिये, क्यों परेशान होते हैं, बैठ जाइये । पहले पूरी बात तो सुनिये न । ध्यानाकर्षण के बाद शेष बचे हुये शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार यादव अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के 8463 पैक्सों में दशकों से प्रबंधक कार्यरत हैं तथा पैक्सों का सफल संचालन करते आ रहे हैं । किन्तु अध्यावधि तक भी सभी पैकस प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से वेतन न देकर पैक्स के लाभांश से वेतन भुगतान की व्यवस्था है । पैक्स को हानि होने की स्थिति में प्रबंधकों का वेतन भुगतान नहीं होता है, जिससे पैक्स प्रबंधकों के परिवार भूखमरी के कगार पर है । सहकारिता विभाग द्वारा निबंधक सहयोग समितियां, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से वेतन के संदर्भ में एक विशेषज्ञ कमिटी का गठन भी किया गया था, जिसे 15.01.2025 तक माननीय मंत्री महोदय को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गयी थी लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है ।

अतः बिहार राज्य के सभी 8463 पैक्स प्रबंधकों को विभागीय स्तर से वेतन भुगतान हो सके, इस संबंध में सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिये ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत करहरिया पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या–7 घोरघट पासवान टोला का सड़क मनी नदी में कटाव के कारण कट जाने से ग्रामीण का रास्ता बाधित हो गया है ।

अतः मनी नदी में कटाव निरोधक कार्य एवं ग्रामीण सड़क बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के नवाबगंज पंचायत में भोरहर स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामलाल मंडल चौक से सोनापुर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है, इसके पुनर्निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के...

अध्यक्ष : एक मिनट, ललन जी एक मिनट । मोबाईल बजता है हाउस के अंदर यह ठीक नहीं है । मेरा आप सबसे आग्रह है अगर सदन के अंदर आते हैं तो मोबाईल बंद करके आइये, ऑफ करके आइये या फिर बाहर अपने प्रतिनिधि को देकर आइये । सदन के अंदर मोबाईल बजता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है । इसका ध्यान रखें आप सबलोग। बोलिये ललन जी ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर पंचायत एवं कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के बकिया सुखाय पंचायत होते हुये बरारी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत तक गंगा नदी पर सड़क पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हुये जातीय गणना के साथ आर्थिक सर्वे रिपोर्ट से आयी गरीबी की भयावह स्थिति से निपटने के लिये 34 प्रतिशत यानी लगभग 95 लाख परिवारों को 2–2 लाख रुपये की राशि एक मुश्त देने तथा पोर्टल तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुण्ड प्रखंड अंतर्गत चन्द्रभानपुर गांव में एक अस्पताल बनाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

टर्न–9 / राहुल / 05.03.2025

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों हिसुआ, नरहट और अकबरपुर में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे में नाम जोड़ने, जॉब कार्ड जारी करने के लिए गरीबों से आवास सहायकों द्वारा हो रही तीन–तीन हजार रुपये की अवैध वसूली की निगरानी जांच की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत गोराडीह एवं जगदीशपुर प्रखंड के 230 वार्डों में पेयजल आपूर्ति हेतु 30 एम0एल0डी0 सतही जल आधारित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत गंगा नदी में Floating jetty एवं Gangway को अधिष्ठापित हेतु योजना प्रस्तावित है, उक्त महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के ममता कर्मी जो रविदास समाज से आती है इनको प्रोत्साहन राशि की जगह प्रतिमाह प्रति ममता कर्मी को बारह–बारह हजार रुपये मानदेय तथा इन्हें राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देने की सरकार से मांग करती हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलांतर्गत धोरैया प्रखंड के पारोहाट से जोठा महादलित टोले तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क काफी खराब एवं जर्जर है जिससे बरसात के दिनों में दर्जनों गांवों का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है । अतः जनहित में उक्त सड़क को अविलंब कालीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी 8463 पैक्स प्रबंधकों का वेतन पैक्स के लाभांश से किया जाता है । हानि की स्थिति में भुगतान न होने से इनका परिवार बेहाल है । सादर आग्रह है कि पैक्स प्रबंधकों का वेतन विभागीय स्तर से किया जाय।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले के लक्ष्मीपुर निवासी मृतक प्रमोद साव को दिनांक–03.03.2025 को नवीनगर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण पिटाई की जिससे उसकी मृत्यु हो गयी जिसका नवीनगर थाना कांड संख्या–67 / 25 है । घटना में शामिल पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर कारवाई एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : आप लिखे हैं 50 लाख बोल रहे हैं 25 लाख । क्या है ?

श्री रणविजय साहू : 50 लाख है सर ।

अध्यक्ष : आप बोले 25 लाख । काट दिये क्या यहां बैठे–बैठे ? आप जो लिखे हैं वही मेरे पास आता है ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, 50 लाख मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद जिलांतर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के मुरहारा पंचायत में रोस्तमचक–धर्मपुर पथ में ज्ञानीविगहा के पास सोइया पईन में पुल नहीं रहने के चलते ग्रामीणों को प्रखंड एवं अस्पताल जाने में 15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है । सरकार से पुल निर्माण की मांग करता हूं।

डॉ0 शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के अंतर्गत चैलाहा से रघुनाथपुर जाने वाली सड़क में धनौती नदी पर चचरी का पुल बना है । बरसात के समय आवागमन पूर्णतः बाधित रहता है जो जिला मुख्यालय को जोड़ती है । अतः सरकार से उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पटना स्मार्ट सिटी, मेट्रो परियोजना और शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर पटना महानगर के सभी निगम अंचलों में फुटपाथ दुकानदारों को बेदखल करने का अभियान जारी है । अतः सदन के माध्यम से इस पर रोक लगाने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत निर्बाध एवं दुर्घटनामुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु सभी बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किये जाने की मांग करता हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलांतर्गत अमौर प्रखंड के सलता से तेलंगा जाने वाली सड़क में संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार कार्य नहीं किया है जिस कारण पक्कीकरण अभी से उखड़ गया है जबकि कार्य पूर्ण किये हुए अभी एक वर्ष ही हुआ है । अतः गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं कराने वाले संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक–03.03.2025 को औरंगाबाद जिलांतर्गत नवीनगर थाना के हिरासत में रखे गये प्रमोद साव की पुलिस की पिटाई से मृत्यु हो गयी । मैं सरकार से दोषियों पर कार्रवाई एवं मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत में गोविंदपुर मुशहरी और कहारपुर गांव का अभी भी मुख्यालय से संपर्क नहीं है । अतः कोशी नदी त्रिमुहान घाट पर पीपा पुल या आर0सी0सी0 पुल बनाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला प्रवास कार्यक्रम 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा साठी को प्रखंड का दर्जा देने की घोषणा की गयी थी परंतु अब तक उक्त प्रखंड का सृजन नहीं हुआ है जिससे क्षेत्र में

काफी आक्रोश है । अतः पश्चिमी चंपारण जिला के साठी में नया प्रखंड सृजित करने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–10 / मुकुल / 05.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, हमें आपको एक सूचना देनी है । आज बिहार विधान सभा के एनेक्सी बिल्डिंग के भूतल पर आप सभी लोगों के लिए सुविधासम्पन्न कैंटीन का शुभारंभ हुआ है । यह कैंटीन पटना के एक प्रतिष्ठित कम्पनी हरि लाल स्वीट्स के द्वारा चलाई जायेगी । यह कैंटीन आपकी व्यस्तता के दौरान गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवायेगी एवं शिष्ट और सौहार्दपूर्ण वातावरण भी प्रदान करेगी । इस कैंटीन में बाजार दर से कम दर पर भोजन सामग्री उपलब्ध होगी, परन्तु क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगी । विधान सभा में जो कैंटीन कार्यरत है, वह पूर्ववत जारी रहेगी यह अतिरिक्त सुविधा आप सब लोगों के लिए, धन्यवाद ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा । इसके लिए दिनांक–05 एवं 06 मार्च, 2025 की तिथि निर्धारित है । वाद–विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल चार घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिये भी समय दिया जायेगा :

भारतीय जनता पार्टी	–79 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	–76 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	–45 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–19 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	–11 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	–4 मिनट

सी0पी0आई0 (एम0)	–2 मिनट
सी0पी0आई0	–2 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	–1 मिनट
निर्दलीय	–1 मिनट
कुल	–240 मिनट

माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन अपना पक्ष रखें । आपका समय 18 मिनट है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, बिहार के वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में 2025–26 का बजट उपस्थापित किया गया है, उसी के विचार–विमर्श के संबंध में मैं अपनी पार्टी का पक्ष आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं, चाहे वह सत्तापक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आज बिहार के अंदर, बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बिहार के अंदर अपराध, बिहार के अंदर महंगाई, बिहार के अंदर पलायन और बिहार के अंदर ये जो सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं से हम सभी लोग ग्रसित हैं और जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो पायेगा, तब तक कोई बेहतर बिहार के निर्माण की संरचना की जो भूमिका हमलोगों को अदा करनी है उसको हमलोग पूरा नहीं कर पायेंगे इसलिए मैं सबसे पहले जो इस बजट के संबंध में सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया और उसमें सरकार ने जो बिहार की जनता के लिए अपनी तरफ से जो घोषणाएं की हैं और जो बजट है उसके संबंध में उसकी क्या त्रुटियां हैं, उसकी क्या कमियां हैं उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा लेकिन इसके पूर्व हमने जिन समस्याओं की चर्चा की, जब तक उन समस्याओं का निष्पादन नहीं हो पायेगा तब तक हमलोग बेहतर बिहार का निर्माण नहीं कर सकते ।

महोदय, आज पूरा बिहार अपराध से ग्रसित है कोई ऐसा दिन नहीं जब बिहार के अंदर हत्या, लूट, पॉकेटमारी और गोलीबारी की घटनाएं नहीं हो रही हैं। प्रतिदिन बिहार के आवाम/लोगों के सामने ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और दुर्भाग्य यह है कि सरकार इन अपराधों पर काबू पाने के बजाय अपनी जिम्मेवारियों से भागने का काम कर रही है और जब हमलोग इस बात को

सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करते हैं तो सरकार के द्वारा जो उनकी गलतियां हैं, जिनकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं उसको झांकने के बजाय दूसरे के ऊपर ही आरोपों का, प्रत्यारोपों का दौर चलाया जाता है और खास करके हमारे दल के लोगों के बारे में यह प्रचारित किया जाता है कि आपके समय में बिहार के अंदर जंगल राज था, आपको बिहार में बढ़ते हुए अपराध के संबंध बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । महोदय, मैं बताना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

बीच में मत बोलिए, जब आप बोलियेगा तो फिर हम भी बोलेंगे और काउंटर होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बोलिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में याद दिलाना चाहता हूं 1990 से 2005 तक बिहार में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार रही थी और एक सामाजिक जन–चेतना और सामाजिक जन–संघर्षों की लड़ाई का दौर उस सरकार के समय रहा था । सभी लोग जानते हैं कि 1990 के दौर में बिहार के अंदर, बिहार में व्याप्त जो कुरीतियां थीं, बिहार के अंदर जो सामंती ताकतें थीं, बिहार के अंदर जो डोली प्रथा थी, बिहार के अंदर जो वर्ग विभाजन था और जिस तरह से लोगों को जातिगत आधार पर तंग व परेशान करने का काम किया जा रहा था, उसके बाद जब बिहार में लालू जी की सरकार आई तो उन्होंने आम जन तक यह संदेश पहुंचाने का काम किया कि बिहार के अंदर जो अंतिम पंक्ति में भी बैठा हुआ व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर के रहने का अधिकार है, उसको भी समान रूप से खाने–पीने, रहने का अधिकार है और जब गरीबों को उन्होंने आवाज दी, उसको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए ताकत दी तो वही सामंती लोग जो थे उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और विरोध के फलस्वरूप बिहार के अंदर बहुत तरह का जन संघर्ष उस जमाने में हुआ । लेकिन वह संघर्ष जो था, वह जन संघर्ष समाज के अंदर जो सच्चाई थी उसको स्थापित करने के लिए था, इसलिए मैं पूरे ईमानदारी के साथ और गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि यदि लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति में नहीं होते तो गरीबों को आवाज नहीं मिलती, उनको लड़ने की ताकत नहीं मिलती और आज इस सदन में जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज इस सदन के अंदर भी नजर नहीं आते इसलिए इस बात को कहकर कि 15 साल के शासनकाल को याद कीजिए आप बिहार के अपराध को नहीं मिटा सकते । बिहार के अंदर जो अपराध की मुख्य पृष्ठभूमि

है उसकी तरफ जब तक सरकार नहीं ध्यान देगी तब तक बिहार को अपराध से मुक्ति नहीं मिल सकती । बिहार के अपराध को रोकने के लिए सबसे जरूरी है बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था की । आज क्या हालात है, बार–बार सरकार के नुमाइंदे, मंत्री और पदाधिकारी कहते हैं कि पुलिस और जनता के बीच आपसी भाई–चारा और सहयोग का वातावरण है, लेकिन जाकर के आप ग्रामीण इलाकों में देखिए जमीनी सच्चाई यह है कि पुलिस आज भी जनता के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर रही है, थानों में उनके रपट नहीं लिखे जाते हैं और बिना कोई नजराना दिये हुए उसका कोई काम नहीं होता है, ऐसी स्थिति में सरकार जो कहती है कि जनता, पुलिस सहयोग के माध्यम से हम अपराध को राकेंगे, इसके लिए आपको अपने पदाधिकारियों पर नकेल कसना होगा और उसके कागजों की समीक्षा करनी होगी । दूसरी बात है कि पुलिस के द्वारा जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है

क्रमशः

टर्न–11 / यानपति / 05.03.2025

(क्रमशः)

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, जब हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं तो पुलिस जनता की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक हथकंडों का सहारा लेकर के जनता का दमन करने का काम करती है । ऐसी स्थिति में बिहार में अपराध नहीं रुक सकता और सबसे बड़ी जो समस्या है, हर जगहों पर सरकार भी स्वीकार करती है और हमलोग भी लगातार इस बात को कहने का काम कर रहे हैं कि बिहार के अंदर अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बिहार में व्याप्त भूमि विवाद है और यह जो भूमि विवाद है इस भूमि विवाद की समस्या का अभीतक कोई ठोस पहल और निदान नहीं हो सका । पूरे देश के अंदर 1972 में भूमि सुधार कानून लागू हुआ और बंगाल सबसे पहला राज्य था जहां भूमि सुधार कानून को शत–प्रतिशत लागू किया गया । लेकिन आज बिहार में 1990 से सरकार कह रही है कि जो असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं उनको हम 5 डिस्मिल जमीन का वासगीत का पर्चा देने का काम करेंगे । पर्चा देने की प्रक्रिया अभीतक समाप्त नहीं हुई और जिनको पर्चा मिला भी है उनको भी जमीन पर कब्जा दिलाने का काम सरकार नहीं कर रही है । आज जो पर्चा लेकर के दर–दर की ठोकर खा रहा है, घूम रहा है, पर्चा दिखा रहा है लेकिन जमीन पर कहीं भी पर्चाधारी लोगों को कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है । और जिनका जमीन पर कब्जा है उनको पर्चा नहीं

दिया जा रहा है और यह बजट जो सरकार ने लाया है उसमें कहीं भी भूमिहीनों को 5 डिस्मिल जमीन देने की कोई भी चर्चा सरकार ने अपने बजट भाषण में नहीं किया है तो सरकार की मंशा को यह दर्शाता है कि ये लोग सिर्फ कागज पर गरीबों की भलाई की बात करते हैं लेकिन जब जमीन पर उसको उतारने की जरूरत होती है तो ये लोग चुप्पी साधने का काम करते हैं । इसीलिए जबतक बिहार में भूमि की समस्या का निदान नहीं होगा, गरीबों को वासगीत का पर्चा नहीं मिलेगा, जिसको वासगीत का पर्चा मिला है उसको जमीन पर कब्जा नहीं मिलेगा, बिहार में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शत–प्रतिशत जबतक लागू नहीं किया जायेगा तबतक बिहार के अंदर बिहार के विकास की कल्पना करना एक कोरी कल्पना होगी और बिहार में अपराध को रोकना भी एक कोरी कल्पना मानी जायेगी । इसीलिए साथियों, भाइयों, अपराध पर हमने इसलिए चर्चा की अध्यक्ष महोदय कि अपराध जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता और कोई भी कितना अच्छा बजट ले आए उसको जब तक अपराध मुक्त समाज नहीं रहेगा, उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा । वही हालत बिहार में भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार बिहार की एक संस्कृति बन गई है, जहां कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाइये, हम समझते हैं कि ईमानदारी से यदि इसका विश्लेषण किया जाय तो यहां पर बैठे हुए सभी लोग इसको स्वीकार करेंगे कि बिहार के सारे सरकारी कार्यालयों में चाहे वह छोटा कार्यालय हो या बड़ा कार्यालय हो, छोटे कर्मचारी हों, बड़े पदाधिकारी हों सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और यह जमीनी सच्चाई है कि जनता का काम बिना नजराना दिए हुए नहीं हो रहा है । इसलिए भ्रष्टाचार पर यह सरकार पूरी तौर पर चुप्पी साधे हुए हैं और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं न्याय के साथ विकास की बात लेकिन न्याय के साथ विकास की बात करने के लिए जब तक उसका भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगा तब तक आप न्याय के साथ विकास की बात नहीं कर सकते । आज प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हो रहा है पूरे बिहार में, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हुए हैं सर्वे करने के लिए हर टोला और गांव में जो आवास सहायक जा रहे हैं खुले रूप से गरीबों से दो–दो हजार, तीन–तीन हजार रुपया वसूला जा रहा है और वसूला जा रहा है सर्वे के नाम पर और कहा जा रहा है कि हम आपको आवास दिला देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत । ऐसे बिचौलिए लोगों पर न कोई सरकारी पदाधिकारी ऐक्शन लेने के लिए तैयार है और न कोई जनप्रतिनिधि बात सुनने के लिए तैयार है । इसलिए भ्रष्टाचार आज बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महोदय, आज जो बेरोजगारी बिहार में है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की दर लगभग 18 प्रतिशत बनी हुई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है । बिहार की कुल

आबादी का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है और राज्य में शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन सरकारी नौकरी की वैकेन्सी नहीं बढ़ाई गई है । 2024 के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में देरी, पुलिस और अन्य विभागों की रिक्तियां नहीं भरी गई हैं । उद्योग क्षेत्र के लिए 53478 करोड़ रुपया आवंटित किया गया लेकिन इसका प्रभाव रोजगार पर कब तक पड़ेगा यह बजट में स्पष्ट नहीं किया गया है । सरकारी नौकरियां देने की बजाय युवाओं को केवल कौशल विकास में उलझाया जा रहा है, कोई बड़ा औद्योगिक निवेश नहीं आया जिसमें निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा हो । इसलिए बिहार में बड़े–बड़े इंवेस्टर्स मीट कराए गए और हमेशा सब्जबाग दिखाया गया कि बिहार के अंदर मल्टी नेशनल कंपनियां आयेंगी, उद्योग धंधे लगायेंगी, बिहार के नौजवानों को काम मिलेगा लेकिन आजतक जमीन पर इसको इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया गया । इसलिए जबतक बेरोजगारी बिहार से दूर नहीं होगा तब तक बिहार के अंदर जो मूलभूत, बिहार के नौजवान जो हैं, जो आज पलायन के लिए विवश हो रहे हैं, बिहार छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम तलाश रहे हैं जब तक इसपर रोक नहीं लगेगी तब तक बिहार के विकास की बात करना बेमानी होगा महोदय ।

अध्यक्ष : केवल दो मिनट है आपके पास ।

श्री राकेश कुमार रौशन : नहीं महोदय, हमारे एक और साथी हैं उनका भी समय है ।

अध्यक्ष : नहीं क्या, आपकी पार्टी ने 18 मिनट दिया है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, हमारे एक और साथी हैं उनका दो–तीन मिनट समय है ।

अध्यक्ष : नहीं, ऐसा आपके कहने से नहीं होगा । आप अपनी बात 2 मिनट में खत्म कीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनदेखी हो रही है । बिहार सरकार ने शिक्षा के लिए 60964.87 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 20035.80 करोड़ का बजट आवंटित किया है लेकिन इसमें कई खामियां हैं । शिक्षा की जो प्रमुख खामियां हैं उसमें शिक्षकों की भारी कमी है । प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लगभग दो लाख पद खाली हैं, बुनियादी ढांचों में राज्य के 358 प्रखंडों में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है । नीतियों में अस्पष्टता है, मिशन नालंदा और मिशन परीक्षा जैसी योजनाओं का जमीनी असर नहीं दिख रहा । स्वास्थ्य की जो प्रमुख कमियां हैं, सरकारी अस्पतालों में अधिकांशतः मशीनों की खराबी और कमी तथा चिकित्सकों की कमी बनी हुई है । चिकित्सक नहीं आते हैं । मैं अपने ही विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा महोदय, हमारे

विधान सभा क्षेत्र में इस्लामपुर और एकंगरसराय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है महोदय लेकिन एक डॉक्टर छोड़कर के प्रतिदिन कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आता है जबकि चिकित्सकों की संख्या लगभग 7 है और जो प्रभारी है महोदय वह भी लगातार अस्पताल में नहीं रहते और एकंगरसराय के जो प्रभारी हैं वह तो पटना से आना–जाना करती हैं, वहां अस्पताल में रहती नहीं हैं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, इसी तरह से जो कृषि और ग्रामीण व्यवस्था है उसकी भी अनदेखी हुई है और इसमें कृषि के लिए बजट में कोई ठोस योजना नहीं है और जो कृषि और सिंचाई के लिए 10 हजार करोड़ प्लस रुपया दिया गया है लेकिन कोई कर्जमाफी......

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : योजना नहीं है महोदय, एम0एस0पी0 पर, अनिश्चिता बनी हुई है. .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह ।

श्री राकेश कुमार रौशन : सरकार ने एम0एस0पी0 नीति घोषित नहीं किया है महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका 15 मिनट है, आप बोलिए, उनको 15 मिनट दे सकते हैं ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय......

अध्यक्ष : रुक जाइये, समीर जी ने अपना दो मिनट उनको देने के लिए कहा है । बोलिए दो मिनट ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, अभी जो वर्तमान बजट है इस बजट में सरकार अपने राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए अधिक उधारी ले रही है । 2025–26 में 55737.79 करोड़ का नया कर्ज लिया जायेगा और पहले से 3.17 लाख करोड़ कर्ज है ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / अंजली / 05.03.2025

(क्रमशः)

श्री राकेश कुमार रौशन : इस तरह से अगर राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो बार–बार उधारी क्यों ली जा रही है ? और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हर महिला के खाता में 2500 रुपया प्रति माह देने की व्यवस्था की जाय चूंकि महिलाएं 60 प्रतिशत कुपोषण की शिकार हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और वृद्धजन पेंशन को 1500 रुपया किया जाय । 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाय और हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं ।

अध्यक्ष : अब बाद में बोलिएगा ।

श्री राकेश कुमार रौशन : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं–नहीं, आपको 2 मिनट टाइम तो दे ही दिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : एक मिनट महोदय । परिमार सिंचाई योजना का पक्कीकरण, इस्लामपुर में सुभाष स्कूल और एकंगरसराय एस0एस0 एकेडमी के मैदान में स्टेडियम का निर्माण, तेलहाड़ा महोत्सव की स्वीकृति और खुदाखंज बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दी जाय महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान सरकार है इनके जो मुखिया हैं वह थके और हारे हुए हैं...

अध्यक्ष : संजय जी, आप बोलिए । आपका समय 15 मिनट है ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमको बजट पर बोलने का जो अवसर आपने प्रदान किया है उसके लिए आपका हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी और अपने सचेतक जनक सिंह जी का जिन्होंने आज हमको बोलने का अवसर दिया और सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद उस लालगंज की महान जनता को जिन्होंने चुनकर इस सदन में बिहार के विषय पर अपनी बात रखने का अवसर हमको प्रदान किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से विषयांतर नहीं होता हूं । आज बजट का विषय है मैं पूरे मनोयोग से था कि आज केवल और केवल बजट पर बोलूंगा परंतु कल नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से 1990 से 2005 तक के शासन का बखान किया और आज जिस प्रकार से रौशन जी 1990 से 2005 तक की सरकार के कार्यों का व्याख्यान हम सब लोगों के सामने रख रहे थे तो हमको लगता है कि पहले उनको स्मरण कराना पड़ेगा और उसके बाद बिहार के इस विकास के बजट के बारे में हमको बात रखनी पड़ेगी ।

(व्यवधान)

आप भटकिए मत, एक–एक विषय पर हम आएंगे । अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 के बीच क्या हुआ ? इसी बिहार ने गौतम और शिल्पी जैसे निर्मम हत्याकांडों को देखा । इसी बिहार ने शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी को, एक व्यक्ति जो पिछड़े समाज का लड़का था उसको ईंट–भट्टे की चिमनी में जलाते हुए देखा, इस बिहार के लोगों ने शोरूम से गाड़ियां उठते हुए देखा, इसी बिहार के लोगों ने चीनी मिलों के उद्योगपतियों के अपहरण होते हुए देखा, इसी बिहार के लोगों ने उद्योगों का पलायन होते हुए देखा और इसी बिहार के लोगों ने एक आई0ए0एस0...

(व्यवधान)

शांत रहिए–शांत रहिए । सुनने का धैर्य रखिए । इसी बिहार के लोगों ने एक आई0ए0एस0 बी0बी0 विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ दो वर्षों तक लगातार बलात्कार होते हुए देखा, यह 1990 से 2005 तक की सरकार थी और उसमें क्या हुआ ? एक आई0ए0एस0 को उस समय में अपनी पत्नी के साथ होने वाले बलात्कार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए...

अध्यक्ष : बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : उस समय के पुलिस के पास दौड़ लगानी पड़ी, यह बिहार का दौर, यह बिहार 1990 से 2005 तक का बिहार की जनता ने देखा है और आदरणीय तेजस्वी जी, चूंकि उस समय वे एक पाठ लेकर आए थे, लालू चालीसा का पाठ लेकर आए थे । आप याद कीजिए, 1990 से 2005 तक किस तरह से आपके लोगों ने पिछड़े और अतिपिछड़े समाज के लोगों की जमीनों पर...

श्री सत्यदेव राम : महोदय, व्यवस्था पर खड़ा हूं ।

अध्यक्ष : क्या है ? एक मिनट संजय जी ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, व्यवस्था यह है कि अभी संजय जी ने कहा कि मैं बजट पर बोलूंगा और जो बोल रहे हैं क्या यही बजट है ।

अध्यक्ष : बैठिए–बैठिए । संजय जी, बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, सत्यदेव बाबू ने ठीक से सुना नहीं ।

अध्यक्ष : आप इधर देखकर बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : मैंने कहा कि मैं बजट पर ही बोलूंगा लेकिन हमको मजबूरन आपको 1990 से 2005 का इतिहास बताना पड़ रहा है, इसलिए कि कल नेता प्रतिपक्ष बजट पर नहीं बोल रहे थे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नहीं बोल रहे थे वे केवल और केवल एक बखान लेकर आए थे कि 1990 से 2005 तक कि आपकी सरकार ने क्या किया ? इसलिए हमको आपको आईना दिखाना पड़ रहा है और आपके नेता चूंकि कम उम्र के हैं, उनको अभी स्मरण नहीं होगा वह जमाना, जिस जमाने में आपके लोगों ने, इस बिहार के पिछड़े और अतिपिछड़े समाज के लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया, बेदखल किया और बहू–बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया, यह काम आपकी बिहार की सरकार में हुआ है । इसलिए हमको आईना दिखाना पड़ रहा है । बिहार के अंदर विकास की गाथा 2005 के बाद लिखी गई और 2005 के पहली की सरकार, शिक्षा में क्या था ? हम देखते थे, हम जब कॉलेजों के अंदर पढ़ते थे तो हम अपने कॉलेज के...

(व्यवधान)

थोड़ा धैर्य से सुनिये । पुराना समय याद कीजिए, उस जमाने को ।

अध्यक्ष : संजय जी, इधर देखकर बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले लोगों में से थे । हमको शर्म आती थी जब हमारे प्राध्यापक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर एक किराने की दुकानदार के सामने गिड़गिड़ाते थे कि हमको जब वेतन मिलेगा तब हम आपके पास पैसा जमा करेंगे, हमारे बच्चों को खाने के लिए, हमारे परिवार को खाने के लिए किराना का सामान दीजिए, छह–छह महीना, आठ–आठ महीना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था, यह आपकी बिहार की सरकार ने किया है । आपकी बिहार की सरकार ने क्या किया है, आप स्मरण कीजिए । आपके जमाने में विद्यालयों में छप्पर नहीं हुआ करता था, छप्पर अगर है तो शिक्षक नहीं होते थे और आज जाकर देखिए चमचमाती हुई बिल्डिंगें आपको दिखाई देंगी । अच्छे शिक्षक दिखाई देंगे, पढ़ते हुए विद्यार्थी दिखाई देंगे और तो और हमारी बहनें जब साईकिल पर बैठकर के मीलों–मील चलकर विद्यालयों में जाती हैं वह दृश्य आपकी आंखों में चुभता है इसलिए आपको दर्द होता है ।

अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 का अगर कल और आज बखान नहीं होता तो वास्तव में हम केवल और केवल बजट पर बोलते लेकिन इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि लगता था जैसे एक सुनहरा बिहार 1990 से

2005 तक चला है चूंकि आपके नेता की उम्र कम है, हमने कहा न कि आपके नेता की उम्र कम है इसलिए आपको, उनको स्मरण नहीं रहता है, उनको जानकारी नहीं है कि कैसे इस बिहार को लूटा गया है और हम यह नहीं कह रहे हैं और तो और उस समय के सरकार के मुखिया आदरणीय लालू जी के सबसे करीबी लोगों में से एक सुभाष यादव जी ने जो कहा है उसको स्मरण कीजिए, बिहार के गुंडाराज को, बिहार के लफंगई के राज को किस तरकस से प्रतिस्थापित किया है और तय मानिए आगे आने वाला जो आठ–नौ महीने का चुनाव है, बिहार की जनता आपको पूरी तरह से सफाया करेगी । कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण आप इतनी संख्या में जीत गए, आप 20–22 की संख्या पर सिमटा दिये जाएंगे आप चूंकि बिहार की जनता जानती है, बिहार के पिछड़ा–अतिपिछड़ा जानती है कि किस तरह से 1990 से 2005 तक आपने बिहार में गुंडा राज स्थापित किया, किस तरह से लफंगा राज स्थापित किया, यह बिहार की जनता ने देखा है ।

अध्यक्ष महोदय, हम जब आज चलते हैं अस्पताल के अंदर तो हमने वह जमाना भी देखा है कि अस्पताल के अंदर भवन नहीं होता था, रंगाई–पुताई करने के पैसे नहीं होते थे और तो और मरीजों को दवाई देने के लिए पैसे तो छोड़िये रंगाई–पुताई जो सरकार नहीं करा सकती वह मरीजों को भोजन क्या देगी, मरीजों को दवाई क्या देगी लेकिन आज जाकर देखिए, किसी भी सदर अस्पताल में देखिए, किसी भी अनुमंडल अस्पताल में देखिए और तो और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है । आज एक–एक व्यक्ति अपनी बीमारी में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है, आज जाकर सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहा है, यह सरकार बनी है, यह सरकार 2005 के बाद अपनी प्रगति की है ।

अध्यक्ष महोदय, हम जब इनसे बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज महुआ में भी स्थापित हो रहा है, हर जिले के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल स्थापित हो रहा है, यह बिहार के विकास का पैमाना तय हो रहा है और अभी हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी ने जो बजट रखा उसमें कहा कि हम पिंक टॉयलेट बनाएंगे, पिंक टॉयलेट की व्यवस्था अपनी माता और बहनों के लिए करेंगे, तो हमारे कुछ सदस्यगण मजाक उड़ा रहे थे कि अब यही काम रह गया है वित्तमंत्री का कि अब शौचालय बनाएंगे । याद कीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम अपनी माता और बहनों के लिए शौचालय बनाकर देंगे तो ऐसे ही लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया था लेकिन इनको दर्द नहीं मालूम है ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / पुलकित / 05.03.2025

(क्रमशः)

श्री संजय कुमार सिंह : हम और आप जैसे लोग जब गांव के अंदर पगडंडियों से गुजरते थे तो हमारी माताएं और बहनें रात होने का इंतजार करती थी कि कब रात होगी और हम शौच करने के लिए सड़कों के किनारे जायेंगे और उस समय आपके और हमारे जैसा कोई व्यक्ति मोटरसाईकिल से, गाड़ियों से जब उधर से गुजरता था तो सड़क के किनारे हमारी माताएं और बहनें शर्म के मारे, बेइज्जती के मारे खड़ी हो जाती थीं । उस ज़लालत और बेइज्जती से निकालकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश के घर–घर तक शौचालय पहुंचाया । वही काम हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, आज पिंक टॉयलेट के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों को सार्वजनिक स्थानों पर जलालत नहीं झेलनी पड़े, बेइज्जती महसूस नहीं हो इसलिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा । आज किसानों के लिए एक–एक स्थान पर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा ।

(व्यवधान)

यह आपको नहीं पचेगा । इसलिए नहीं पचेगा कि अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं हैं । ये विनाश वाले लोग हैं, ये विकास से दूरी बनाकर रखते हैं और आज जो हमारा इतना बड़ा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखिये । आप उधर ध्यान मत दीजिए, इधर देखकर बोलिये ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कितना न्याय किया, रौशन जी को आपने दो मिनट और बढ़ाकर के समय दिया और अभी अवध बाबू हमको टोक रहे थे और जब आसन पर वे थे तो जैसा आपने हमको कहा 15 मिनट बोलने का समय है । उस समय हमको 10 मिनट समय आवंटित किया गया था ।

अध्यक्ष : अब पांच मिनट समय बचा है आपका । अपनी बात बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार सिंह : एक मिनट हमको अध्यक्ष महोदय ने....

अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार सिंह : सत्यदेव बाबू, आप बुजुर्ग आदमी है । हम पहली बार जीतकर आये हैं, सुनिये तो ध्यान से ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संजय जी, वे आपका समय खत्म कर रहे हैं, आप इधर देखकर बोलते रहिये ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय किया, अभी राकेश जी का दो मिनट समय उनका बचा था उनको समय मुहैया कराया कि आप बोलिये । लेकिन उसी आसन पर हमारे अवध बाबू बैठे थे, हमको सचेतक की ओर से दस मिनट का समय आवंटित किया गया था ।

अध्यक्ष : यह सब बात ठीक नहीं है । आप अपनी बात बोलिये ।

श्री संजय कुमार सिंह : ठीक है । उस समय विषय को रोका गया, उस समय बातें रखने नहीं दी जाती थी । आज आपको धन्यवाद हैं कि आप समय पर हम सब लोगों को बोलने का अवसर दे रहे हैं । आज प्रत्येक जगह डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है, हमारी बहनों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा । तैयारी हमारी थी लेकिन हमने कहा, सौरभ जी हमने कहा कि आपके नेता कल जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहे थे, जिस तिलमिलाहट के साथ बोल रहे थे उसका जवाब उनको मिलना जरूरी है इसलिए उन्होंने 1990 से 2005 की सरकार को नहीं देखा था इसलिए यह बताना पड़ रहा है । कल हमारे साथी ने ठीक कहा था कि बिहार के लोगों ने एक अशिक्षित महिला को मुख्यमंत्री बनते देखा है एक सबसे कम उम्र के व्यक्ति को, एक अनपढ़ व्यक्ति को, एक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं व्यक्ति को बिहार का प्रतिपक्ष का नेता बनते हुए देखा हैं।

(व्यवधान)

आप अपने नेता को समझाइये जो कल बोल रहे थे तो उनको क्यों नहीं टोका। आप में से किसी की हिम्मत थी उनको कहने कि आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलिये । यह आपमें से किसी कि हिम्मत थी उनको कहने की, आप नहीं बोल सकते हैं इसलिए कि उनको आईना दिखाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट के ऊपर हम अपना समर्थन, पार्टी की ओर से पूरा समर्थन करते हैं और बिहार की जनता के लिए जो यह लोक कल्याणकारी बजट आया है, जिसमें किसानों की भी अपेक्षाओं को पूरा करने का और जहां अभी तक हमलोग मूंग, उड़द और बाकी दलहन की चीजों को एम0एस0पी0 पर नहीं खरीदते थे उसका भी प्रावधान किसानों के लिए किया गया है । प्रखंडों में

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी, अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी, यह हमारी सरकार किसानों के लिए कर रही है । नौजवानों के लिए हर प्रखंड में एक प्रखंड स्तरीय खेल का मैदान विकसित किया जाएगा, स्टेडियम विकसित किया जाएगा । साथ–साथ प्रत्येक पंचायत के नौजवानों के लिए ताकि वे हृष्ट–पुष्ट हो सके, इसके लिए प्रत्येक पंचायत में भी खेल मैदान का विकास किया जा रहा है । यह हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार डिग्री कॉलेज खोल रही है । हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रही है । हमारी सरकार नौजवान से लेकर, किसान से लेकर, महिला तक की भागीदारी कर रही है और आप 2500/– रुपये की माई–बहन की योजना लेकर आ रहे हैं । आप शर्म करिये, आपकी सरकार के समय में माइयों और बहनों की जो इज्जत लूटी जाती थीं उन माई–बहनों को 2500/– रुपये देकर उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, वह आप अपने माथे पर का कलंक नहीं मिटा सकते, अगर यह करना भी होगा तो हमारी सरकार करेगी । हमारी सरकार उन माताओं और बहनों के सम्मान के लिए कुछ राशि अगर भेजनी होगी, कुछ सम्मान करना होगा तो यह हमारी सरकार करेगी, हमारे लोग करेंगे यह हमेशा ध्यान रखिये । आज जाकर देखिए, आज पथ के निर्माण की क्या स्थिति है ? पहले हम हाजीपुर में रहते थे, मोतिहारी में रहते थे, मोतिहारी से अगर पटना आना है तो दिनभर का समय रखना है कि मोतिहारी से हमको पटना चलकर आना है । आज क्या स्थिति है ? पटना से मोतिहारी जाना है, मोतिहारी से लौटकर पटना जाना है और उसके बाद भी आपके पास समय रहेगा और आप फिर मोतिहारी तक की यात्रा कर सकते हैं, इतनी अच्छी सड़क हमारी सरकार ने बनायी है । आगे भी वे करेंगे ।

अध्यक्ष : आपके पास केवल दो मिनट शेष है ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, पांच घंटे में हमने पूरे बिहार के एक–एक कोने से लोगों को राजधानी तक पहुंचाया है । अगर हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि चार घंटे में हम राजधानी के किसी भी कोने से लोगों को राजधानी पहुंचायेंगे तो यह तय मानिये कि हमारी सरकार निश्चित रूप से वह भी काम करेगी । आज गांव के अंदर जाकर देखिये, एक–एक सड़क बन रही है । आपके इलाके में भी अगर हिम्मत है तो अब बिहार की सरकार जो सड़कें बना रही है, उन्हें आप रोक तो दीजिए अपने क्षेत्र में, देखिए जनता कैसा आपका उपाय करती है। इसलिए सरकार के बदौलत, इसी सरकार के विकास के बदौलत आप जनता के बीच पूजे जा रहे हैं । लेकिन जनता समझ गयी है पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग समझ गये हैं कि अगर वह सरकार लौटेगी तो फिर वही 1990 और 2005 का शासन लौटेगा । जिसमें केवल गुण्डई होगी, केवल लफंगई होगी, विकास की बात कोसों दूर रहेगी ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हम बजट के अवसर पर अपनी बात कहते हुए और एक बार पुनः लालगंज की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपने नेता सम्राट चौधरी जी और अपने सचेतक महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ, आपका समय 13 मिनट हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बजट पर सामान्य विमर्श में हिस्सा लेने के लिए अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने दल को तथा आपको भी धन्यवाद देता हूँ । महोदय, लगातार यह देखा जा रहा है, पहले हमारे सुशील मोदी जी कभी वित्त मंत्री रहे, जब पहली बार वित्त मंत्री बने तो उन्होंने पहली बार कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत को एक रूपया नहीं देंगे, पूर्व की सरकार ने खजाना खाली किया है । मेरा मानना है कि सरकार का जो पहला बजट की किताब मिलती थी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी का हमें अच्छा लगा, सब चीज अच्छा लगता है लेकिन बजट कि किताब पतली क्यों हो जाती है ? पिछली जो बजट की किताब थी उस बजट से भी पतली हो गयी । क्या कुछ चुराये, क्या चुराये ? यह खुद ही आप समझ सकते हैं ।

अध्यक्ष : गागर में सागर है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, हां सागर में सागर के साथ क्योंकि कहीं न कहीं हम समझते हैं कि हरेक आदमी को जैसे पहली बार अगर कोई वोटिंग का राईट मिलता है तो वह 18 वर्ष में मिलता है । आज के बच्चों को कहा जाएगा कि जो पहली बार हमारा वोटर बनेगा उसको 20 साल पहले की कहानी कहियेगा तो वह नहीं जानता है । वह पहला जो वोटर बना है वह जानता है कि कब हम जन्म लिये, किस स्कूल में पढ़ें, किस शहर में रहे, कहां क्या समस्या है ? अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि विधान सभा की जितनी भी कमेटियां हैं उसका आप सबसे पहले, हम आग्रह करेंगे कोई कमेटी कहीं बिहार में नहीं जाए ।

(व्यवधान)

यह बजट का ही पार्ट है । आप क्यों बोल रहे हैं ? हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई कमेटी जाती है तो उसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं, आंख से देखते हैं और देखने के बाद वहां जो चिंतन, मनन करते हैं, ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब हम जाते हैं मरने के स्थान पर और उस शमशान घाट पर तो वहां जो सोचते हैं कि मरने के समय में हम अच्छा–अच्छा

काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे । अच्छा, गलत काम नहीं करेंगे अंत में यही आना है। लेकिन वहां से आने के बाद वही चीज मन में आती है, लोक–विचार बदल जाते हैं । अगर यह सरकार पांच साल का, 20 वर्ष तक की सरकार, अगर अपने–अपने पांच साल का कार्यकाल देखें, अपने ही तुलना अपने में करें तो ज्यादा अच्छा है । जो आज के लोग चाहते हैं, जो लोग अनुभवी हैं । अब हमारे पिता जी 1966 में विधायक बने और 1966 की बात हम करेंगे तो हमें बचपन की याद है । कोई रिक्शा वाला अगर स्टेशन से एम0एल0ए0 फ्लैट में आता था और वह फ्लैट इस तरह का बना हुआ था जो बी0जे0पी0 पार्टी ऑफिस के सामने है कि रिक्शा वाला को लगा देता था और वह व्यक्ति कौन था, यह मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन आता था और बचपन में जब देखते थे दो घंटा तक मालिक पांच रूपया दे दीजिए, उसको पांच रूपया लोग नहीं देता था।

(क्रमशः)

टर्न–14 / अभिनीत / 05.03.2025

..क्रमशः..

श्री समीर कुमार महासेठ : इधर फ्लैट से उधर घुस जाता था और उधर से इधर घुस जाता था और बोलने के बाद चार जूता मारता था उसको कि पांच रुपये लेगा । जब सरकार, लालू जी की सरकार आयी तब वह जो उलट कर बोलता था कि तुम मार कर देख लो, तब लगता था तुमको लालू ने मन बढ़ा दिया है । लालू ने क्या किया है, मन बढ़ा दिया है और तब लगता था हमलोग, बचपन से कि क्या हो रहा है ? लेकिन जब हम राजनीति में आये तो हमें मुक्तिधाम की बात याद आती है कि जब हम किसी जनाजा को लेकर जाते हैं उस स्थल पर कुछ और सोचते हैं और वहां से आने के बाद कुछ और हो जाता है । खैर मुझे कहना है कि 2025–26 का जो बजट है, यह समाज के दबे–कुचले लोगों की उपेक्षा का बजट है । क्यों ? मैं बताना चाहता हूं कि बजट में जो प्रावधान किया गया है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग सहित जन सरोकार के लगभग सभी विभागों में कटौती की गयी है । मैं 2024–25 और 2025–26 की तुलना सदन में करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा पीछे जाने पर दिक्कत होगी ।

महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग का 2024–25 का बजट 01 लाख 95 हजार 305 रुपये से घटाकर 01 लाख 93 हजार 564 रुपये कर दिया गया । पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का 2024–25 के बजट में 01 लाख 80 हजार 713 रुपये से घटाकर 01 लाख 78 हजार कर दिया गया । समाज कल्याण विभाग जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त करने का विभाग है उसका 2024–25 में बजट प्रावधान 13 लाख 63 हजार 935 रुपये से घटाकर 08 लाख 77 हजार 462 रुपये कर दिया गया ।

अब बताया जाय । आगे बढ़ते हैं लगातार हम देख रहे हैं बिहार में कृषि आधारित राज्य है उसके भी बजट को उन्होंने घटाया । कृषि विभाग का 2024–25 का बजट था 04 लाख 12 हजार 684 रुपये उसे 2025–26 में घटाकर 03 लाख 52 हजार 822 रुपये कर दिया गया । कृषि से ही जुड़ा हुआ पशु एवं मत्स्य विभाग है । पशुपालन के नाम से बहुत बदनाम हो गया तो डिपार्टमेंट को कर दिया गया पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग । अब आइये, उसका भी 2024–25 में जो बजट प्रावधान था 01 लाख 97 हजार 852 रुपये उसे भी घटाकर 01 लाख 78 हजार 147 रुपये कर दिया गया । इसी तरह भवन निर्माण में 2024–25 में बजट प्रावधान था 08 लाख 88 हजार 901 उसे भी घटाकर के 06 लाख 89 हजार 467 कर दिया गया । यही नहीं महोदय, बिहार संस्कृति के मामले में काफी आगे है लेकिन कला संस्कृति युवा विभाग के भी बजट में कटौती कर दी गयी । 2024–25 में बजट प्रावधान था 27 हजार 744 रुपये उसे घटाकर 27 हजार 718 रुपये कर दिया गया । इसी तरह पंचायती राज, चूंकि पंचायती राज के 2024–25 के बजट में 11 लाख 95 हजार 443 था उसे भी घटाकर 11 लाख 30 हजार 251 कर दिया गया । महोदय, इन्होंने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, चूंकि बिहार कहां है किसी से छिपा हुआ नहीं है इसलिए हमने कहा कि सारी कमेटी को बिहार भ्रमण छोड़ देना चाहिए । जैसे वित्त विभाग, इस विभाग का एक था कि लोग गुणवत्ता को देखने के लिए इनके यहां से ऑडिट विभाग होता था, ऑडिट विभाग ही खत्म हो गया । हरेक डिपार्टमेंट का ऑडिट होता था, लोग डरते थे तो ऑडिट विभाग ही खत्म हो गया, वित्त विभाग में चला गया, इसका मतलब है कि जिनको भी देखने की क्षमता है उनको समाप्त कर दिया । आज ऑपोजिशन के हाथ से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ऑपोजिशन को ही समाप्त कर दिया जाय । पता नहीं कहां से कहां राजनीति में कितनी और गिरावट होने वाली है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन चालिए अपने बजट पर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है नहीं तो संजय भाई फिर गड़गड़ाने लगेंगे । 02 लाख 05 हजार 318 से घटाकर 01 लाख 31 हजार कर दिया गया ।

हम प्रदूषण की बात कह रहे हैं और चर्चा भी हो रही थी, राज्य प्रदूषण से कराह रहा है लेकिन उसकी चिंता उन्हें नहीं है । पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 2024–25 का बजट था 01 लाख 04 हजार 371 उसे भी घटाकर 90 हजार 688 कर दिया गया है । महोदय, लोक स्वास्थ्य का सारा दरोमदार सरकार पर है, चूंकि किसी पेसेंट को अगर लेकर जाइयेगा तो पेसेंट ट्रॉली को लेकर जाइयेगा किसी हास्पिटल में तो बायें–दायें देखेगा कि कोई 100 रुपये 200 रुपये देगा तब आपके स्ट्रेचर को लेकर जायेगा और गलती से टॉयलेट लग जायेगी, ऐसा पेसेंट है जिसका पेट खराब है तो टॉयलेट के लिए वहां पर जो आप संविदा पर रखे हुए हैं वह टॉयलेट नहीं करायेगा । एक बार यूरिनल कराने के लिए 100 रुपये दीजिए और 300 रुपये प्रति टॉयलेट कराने के लिए दीजिए, तो यही अभी सरकार का चल रहा है, जो आप अपने भी पेसेंट को लेकर के, हम तो भगवान से कहते हैं कोई बीमार मत पड़िए या किसी को लेकर मत जाइये, लेकिन लेकर जाइये तो जो दृश्य हम देखते हैं वही दृश्य दर्शा रहे हैं कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं और कोई भी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीन मिनट बाकी है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, लोक स्वास्थ्य के साथ निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग का भी बजट जब 21 लाख 14 हजार 515 से घटाकर 20 लाख 03 हजार 580 कर दिया गया । शिक्षा विभाग के 2024–25 के पुनरीक्षित बजट में 77 लाख 58 हजार 318 से घटाकर 60 लाख 96 हजार 641 कर दिया गया । महोदय, श्रम संसाधन विभाग का वही हाल है । बिहार राज्य आपदा विभाग में भी वही हाल है । क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा जो पुराना था मोटा अब वह आधा हो गया है, तो कहने का मतलब एक तरफ जो हम दिखा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं यह हम चर्चा करना चाह रहे हैं आगे का कि बजट बनाते समय पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं और पिछला लगातार हम यही देख रहे हैं कि जो भी पैसा आप देते हैं खर्च नहीं हो पा रहा है । क्यों सर, हमलोग को भी स्टीमेट कमेटी में रखे हुए हैं । मत रखिए, उससे हटाकर दूसरी कमेटी में डाल दीजिए । चूंकि जहां पर हमलोग गांव में गये, 12 जिलों में गये और नल–जल योजना को देखने गये तो पता चल रहा है कि जल कहीं है, नल कहीं है, पानी तो जनता को मिल ही नहीं रहा है । आखिर क्यों ? हम उस समय भी हल्ला किये थे कि जबतक उतने पैसा का सब जगह चापाकल..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हल्ला कोई नहीं करता है, शोर करता है । बोलिए, जारी रखिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, बजट बनाते समय लंबा–चौड़ा है लेकिन खर्च नहीं कर पाते हैं । महोदय, इनका स्थापना प्रतिबद्ध व्यय लगातार बढ़ रहा है । 2021–22 में 01 लाख 09 हजार 825 करोड़ था 2025–26 में 01 लाख 26 हजार 749 करोड़ हो गया । महोदय, 2023–24 में 01 लाख 50 हजार 247 करोड़ से 2024–25 में 01 लाख 78 हजार 607 करोड़ हो गया । 2025–26 में इनके कुल बजट में से योजना मद में 01 लाख 16 हजार 759 करोड़ में स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मद में 02 लाख 01 हजार 135 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । महोदय, यह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इनको इतना ऋण लेने की पात्रता है । कोई भी व्यक्ति ऋण पात्रता से नहीं लेता बल्कि जोर से लेता है । इस प्रकार ऋण लेने की प्रवृत्ति का नतीजा राज्य पर बुरा असर पड़ेगा । ''ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत'' वाली कहावत पर मत चलिए । 2021–22 में 02 लाख 27 हजार 195 करोड़, 2021–22 में 02 लाख 57 हजार 510 करोड़, 2022–23 में 02 लाख 93 हजार 307 करोड़, 2023–24 में 02 लाख 68 हजार 613 करोड़, 2024–25 में 02 लाख 97 हजार 909 करोड़ और 2025–26 में जो अनुमानित होगा, 03 लाख 32 हजार 740 करोड़ का ऋण भार है। महोदय, अब मैं अपने..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : क्षेत्र की कुछ समस्याओं को कहना चाहता हूं । क्षेत्र की समस्या को कहे बिना हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ हमारे यहां भी जैसा पिछली बार हमने चर्चा की..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट है जल्दी बोल दीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : वन विभाग और सड़क विभाग में दो सड़कें हमारी थी । वन विभाग वर्सेज सड़क में चल रहा है, नगर विकास वर्सेज सड़क में, इसलिए वन विभाग, तीनों मंत्री मिलकर आपस की समस्या का निदान करें और बिहार का जो पांच साल से चल रहा है जिस टाइम में आप पैसा देते हैं, जो दो साल में कम्पलीट करना है वह पांच–पांच साल से पड़ा हुआ है पूरे बिहार में । 17 सड़क जो हैं हम समझते हैं कि एन0एच0 के पड़े हुए हैं, हरेक जिले का पड़ा हुआ है और जहां उस समय जो चर्चा हो रही थी नगर विकास का भी पड़ा हुआ है, इसलिए जो हमारे मधुबनी का है, जो सबसे बड़ा पूरे देश–दुनिया में सबसे ज्यादा क्राप्ट विलेज के नाम से मधुबनी में जितवारपुर है, हम समझते हैं कि वह सबसे बेस्ट है । पूरी दुनिया में उससे बड़ा अवार्ड कहीं का नहीं मिला,

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मधुबनी से लेकर के उसको पूरा करने के लिए और मधुबनी सड़क में सिरहनिया चौक से सूरी हाई स्कूल वाया...

..क्रमशः..

टर्न–15 / हेमन्त / 05.03.2025

श्री समीर कुमार महासेठ : (क्रमशः) : महाराजगंज तक और आर0के0 कॉलेज से लेकर बुबना उद्यान तक दो सड़क हैं जिसको बनवाने की कृपा करेंगे । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री ललित नारायण मंडल । दस मिनट का समय है आपके पास ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा में प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, श्रवण बाबू और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस विधान सभा में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सुल्तानगंज की महान जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि हमको विधान सभा में कुछ बोलने का मौका मिला है ।

महोदय, 24 नवम्बर, 2005 से जब से नयी सरकार बनी है पूरे बिहार की जनता देख रही है कि बिहार का विकास हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है । चाहे शिक्षा की बात कीजिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कीजिए, चाहे बिजली विभाग की बात कीजिए, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में सरकार विशेष ध्यान दे रही है । सर, हम कॉलेज शिक्षक रहे हैं । हमको याद है वह जमाना, जब हमको सात–आठ महीने वेतन नहीं मिलता था । हम लोग हड़ताल करते थे, तो पटना से कहा जाता था – माल महाराज का मिर्जा खेले होली । हम उस जमाने को भी याद करते हैं और आज सरकार शिक्षकों को समय पर वेतन दे रही है, कॉलेज में शिक्षक की बहाली हो रही है। स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में हर जगह बहाली हो रही है और सबको वेतन मिल रहा है । इसके लिए मैं सरकार को आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूं ।

महोदय, पहले बिहार में मात्र 42481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे वर्तमान में इसकी संख्या 105000 हो गयी है जिसमें 30 हजार से अधिक महिलाएं हैं । जो महिलाएं पहले असुरक्षित रहा करती थी, शिल्पी–गौतम की घटना जहां पर होती थी, आज वही शिल्पी हम लोगों की सुरक्षा में बन्दूक और रायफल लेकर

सड़क और गलियों में घूमकर बिहार की रक्षा करती है । इसके लिए मैं सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, आज अपराध नियंत्रण के लिए 112 डायल कीजिए, तुरंत पुलिस हाजिर हो जाती है और आपकी समस्या को सुनती है और आपको जो समस्या हो उसका हल भी करती है । हम यह नहीं कहते कि अपराध बंद हो गया है । अपराध बंद होने की चीज नहीं है, बंद नहीं हो सकता है, अपराध होता है, लेकिन सरकार द्वारा उसका निवारण भी किया जाता है । घटनायें घटती हैं, लेकिन तुरंत उसका निवारण सरकार के द्वारा, पुलिस–प्रशासन के द्वारा किया जाता है । यह भी सरकार की उपलब्धि है । सरकार ने सामाजिक सौहार्द के लिए और साम्प्रदायिक सौहार्द का भी माहौल कायम है । हम भागलपुर यूनिवर्सिटी के टीचर रहे हैं । वहां पर दंगा होता था । हमेशा डर लगता था कि पता नहीं कब दंगा हो जायेगा, लेकिन आज भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में कहीं भी कोई भय नहीं लगता है, कहीं दंगा का माहौल नहीं है । सब अमन–चैन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अमनचैन से जी रहे हैं । इसके लिए भी मैं इस सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, पहले 8 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है । हम लोगों से भी लिस्ट मांगी गयी है, हम लोगों ने भी लिस्ट दी है और शेष कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी होनी है । उसी प्रकार हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी हो रही है । पहले हिंदू मंदिरों की घेराबंदी नहीं होती थी, लेकिन इस सरकार ने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी की व्यवस्था की है जिससे कि सामाजिक सौहार्द बना रहे ।

महोदय, शिक्षा पर कितना विशेष ध्यान दिया गया है । यह हम सब लोग जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और स्कूल जाता है उसी वक्त उसको पोशाक मिलती है, आहार मिलता है, किताब मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं । महोदय, आज यह स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं हैं । सभी शिक्षकों की बहाली हो गयी है और गांव, सुदूर गांव में अच्छे–अच्छे शिक्षक जाते हैं पढ़ाने के लिए और बच्चे मन लगाकर वहां पढ़ रहे हैं । इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं । अब तक दो बार में 253000 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन गये हैं । स्वास्थ्य सेवा पर भी विशेष ध्यान है । एक जमाना था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को पुर्जा लिखने के लिए कागज नहीं होता था, थानेदार को एफ0आई0आर0 करने के लिए पेपर नहीं होता था, कहता था कि बाजार से दो पेज पेपर लाइये तब हम एफ0आई0आर करेंगे, तब हम पुर्जा लिखेंगे, लेकिन अब जिस भी हॉस्पिटल में जाइये वहां पर पेशेंट भरा पड़ा रहता

है, उसका इलाज होता है । वहां डॉक्टर हैं, वहां नर्स हैं, वहां दवाई फ्री मिलती हैं और वही स्थिति थानेदार की है । थाना में जाइये वहां कोई थानेदार आज आपसे नहीं कहता है कि कागज बाजार से लाइये, कार्बन बाजार से लाइये । आज वहां सभी चीज उपलब्ध है और लोगों को न्याय मिल रहा है । इसके लिए भी हम सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं ।

महोदय, पहले टार्गेट था कि सुदूर बिहार से पटना छः घंटे में आना है, लेकिन अब सरकार ने उसको बदलकर पांच घंटा कर दिया है । इतना रोड बना है, हम तो अपने विधान सभा की बात करते हैं, हर गांव को हम लोगों ने रोड से जुड़वा दिया है । एक भी गांव नहीं बचा हुआ है जिसे सड़क से न जोड़ा गया हो। महोदय, एन0एच0 की भी स्थिति बहुत अच्छी है और फोरलेन इतना बन रहा है कि समझ में नहीं आता है, लगता है कि सारी जमीन रोड में ही चली जायेगी । इतना विकास हो रहा है सड़क के मामले में । इसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : दो मिनट और हैं आपके पास ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, जब दो ही मिनट बचे हैं, तो हम अपने क्षेत्र की भी कुछ बात करते हैं । पहले हम अपने मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी धन्यवाद देते हैं कि सुल्तानगंज में इन्होंने हवाई अड्डा देकर हम लोगों को गौरवान्वित किया है । हम बिहार सरकार को इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं ।

महोदय, सुल्तानगंज में गंगा रिवर फ्रंट बन रहा है और गंगा फिर से उत्तरवाहिनी होने वाली है । इसके लिए भी हम बिहार सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं । 1800 करोड़ की हम लोगों ने डिमांड की थी, 1800 करोड़ से गंगा जल को लिफ्ट करके बढ़िया डैम में और जलाशय में डालकर उसको फिर सिंचाई की व्यवस्था करने की बात सरकार ने स्वीकार की है । इसके लिए भी हम बिहार सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं ।

महोदय, हम अपने क्षेत्र के डिमांड की बात करते हैं । सर, हमारे यहां दो प्रखण्ड हैं । सुल्तानगंज प्रखण्ड और शाहकुंड प्रखण्ड । सुल्तानगंज प्रखंड में अंगीभूत महाविद्यालय है, जहां पर कि मैं शिक्षक रहा हूं, लेकिन शाहकुंड प्रखंड में एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है । सरकारी नीति के अनुसार उस प्रखंड में एक अंगीभूत महाविद्यालय बनना चाहिए । हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय बात सुन रहे हैं, शाहकुंड में एक भी महाविद्यालय नहीं है । वहां पर एक अंगीभूत महाविद्यालय बनाने की कृपा कीजिए जिससे क्षेत्र की जनता का विकास हो जाय ।

महोदय, सुल्तानगंज बाजार में एक महिला अस्पताल है जहां पर पहले बहुत अच्छी सेवा दी जाती थी, लेकिन आज सब सेवा रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज में उपलब्ध है । लेकिन हम चाहते हैं कि बाजार में होने के कारण उस महिला हॉस्पिटल का भी उद्धार किया जाय जिससे कि प्रसव के दौरान जो अगल–बगल की महिलाओं को सुविधा मिले । महोदय, अंत में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को आपने महत्व दिया है उसी तरह अंगिका को भी आप महत्व दीजिए और अंगिका भाषा में भी आप मध्य विद्यालय में, उच्च विद्यालय में और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली कराइये बीपीएससी के माध्यम से । बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री मुरारी मोहन झा । पंद्रह मिनट समय है आपका ।

टर्न–16 / धिरेन्द्र / 05.03.2025

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और...

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्रीमती ज्योति देवी जी ने आसन ग्रहण किया)

आदरणीय श्री जनक सिंह जी जो हमारे मुख्य सचेतक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ । सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता को जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर मुझे इस सदन में खड़ा होकर बोलने का मौका दिया ।

महोदया, मैं कल नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था और वे जो बखान अपना कर रहे थे, उनके पिता जी के शासनकाल का वर्ष 1990 से 2005 तक का, मुझे आश्चर्य होता है । कारण, पता नहीं उस समय इनकी उम्र क्या रही होगी, अगर उम्र भी रही होगी तो पता नहीं वे कहाँ रहते होंगे, उन्हें पता नहीं बिहार की क्या स्थिति थी ? यहाँ के लोगों ने देखा है, यहाँ के लोगों ने झेला है । महोदया, जिसका नतीजा था कि आज बिहार के नाम पर पूरा देश शर्मसार था, कोई बिहार आना नहीं चाहता था, बाहरी लोग बिहार आना नहीं चाहते थे और यहाँ के सभी व्यापारी यहाँ से पलायन कर बिहार छोड़ कर अन्यत्र जगहों पर भागने को मजबूर थे । महोदया, निश्चित रूप से जो....

(व्यवधान)

कारखाना आप भी देख रहे होंगे चश्मा उतारियेगा तब न दिखाई देगा आपको । देख ही नहीं रहे हैं, चश्मा उतारिये तब न बुझायेगा ।

महोदया, निश्चित रूप से वह जो कार्यकाल था जो यहाँ की जनता ने जंगलराज का संबोधन किया वह कोई गलत नहीं था । निश्चित रूप से वह 15 साल का कार्यकाल लगता था बिहार में जैसे पूरा बिहार अंधकारमय है । कहीं भी न सड़कें थीं, न कहीं 24 घंटा बिजली आ पाती थी, एक–दो घंटा मुश्किल से बिजली आ पाती थी और आज की स्थिति वे सब भी देख रहे हैं सदन में बैठ कर और पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है । निश्चित रूप से हमलोग दरभंगा से अगर समस्तीपुर जाने के लिए भी निकलते थे तो 04 घंटा का समय 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता था तो वह कार्यकाल इनको याद करना चाहिए । चाहे हॉस्पिटल हो, अस्पताल में कहीं कोई डॉक्टर का अता–पता नहीं रहता था और हमारे यहाँ दरभंगा जिला में इतने नामी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ की जो दुर्दशा थी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ तो निश्चित रूप से 20 साल में यह परिवर्तन हुआ है, आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है । महोदया, उस काल में अगर आप देखें तो कुछ ही व्यापार यहाँ चल रहा था लूट, अपहरण, बैंक डकैती यही उद्योग बनकर उस समय रह गया था । निश्चित रूप से आज जो परिवर्तन हुआ है आदरणीय श्री नीतीश जी के, एन॰डी॰ए॰ के कार्यकाल में वह देख कर ये लोग घबराये हुए हैं । वे लोग समझ रहे हैं अपने आप को कि ये चूंकि सत्ता से काफी दूर चले गये हैं और निश्चित रूप से जो सदस्यों ने कहा है कि इस बार आने वाले चुनाव में इनकी जो स्थिति होगी वह देखने लायक रहेगी ।

सभापति महोदया, निश्चित रूप से, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बजट आकार, समग्र बजट पेश किया गया है, इसमें चौतरफा विकास का चिंतन हुआ है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास का विशेष ध्यान रखा गया है । बिहार का लगभग 03 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का वर्तमान बजट से स्पष्ट है कि किस प्रकार यह बजट सरकार के सामाजिक क्षेत्र और ढांचागत विकास को स्थापित किया है । महोदया, इस बजट के अंतर्गत महिलाओं, युवाओं सब का चिंतन मनन हुआ है । आज आपका ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहेंगे एवं राज्य के विकास के लक्ष्यों की प्रप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा दिये गये मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प 'न्याय के साथ विकास' राज्य के विकसित परिकल्पना को साकार करने वाले बजट पर, सभापति महोदया, मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ ।

हर बार चुनौतियों को ऐसे हराते हैं हम,

जख्म जितना गहरा हो उतना मुस्कुराते हैं हम ।

महोदया, आज वही प्रश्न खड़ा करते हैं जब खुद की सरकार थी, वर्ष 2005 में तो उनकी सरकार का कुल बजट 23,885 करोड़ रुपये का था, उससे कई गुणा ज्यादा एन०डी०ए० सरकार में 60,954 करोड़ रुपये सिर्फ शिक्षा का बजट है । महोदया, एन०डी०ए० सरकार में वित्तीय वर्ष 2024–25 में 02 लाख 79 हजार करोड़ रुपये का बजट था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025–26 में 03 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट है जो वित्तीय वर्ष 2024–25 से 38 हजार करोड़ रुपये अधिक है । महोदया, न केवल बिहार के बजट में वृद्धि हुई है बल्कि एन०डी०ए० सरकार में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है । महोदया, जब उस कार्यकाल की बात करके, सड़कों की दुर्दशा लोगों ने झेली है, देखी है और अगर उस समय जो हमारे नेता थे बिहार के वे स्वयं भी बोला करते थे कि हमारे लोग सड़क पर नहीं चलना चाहते, हमारे लोग बैल गाड़ी पर चलते हैं वही हमारे मतदाता हैं इसलिए सड़क की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है तो महोदया, जिनकी सोच ऐसी थी तो समझ सकते हैं, उनका बखान करने वाले उनके सुपुत्र कल बयान दे रहे थे और बखान कर रहे थे । महोदया, वर्ष 2005 से पहले की सरकार में ग्रामीण सड़कें टूटी–फूटी अवस्था में थी, सड़क पर पैदल चलना मुश्किल था, बिहार गड्ढों वाली सड़कों के लिए बदनाम था । वर्ष 1990 से 2005 तक सड़क का निर्माण न के बराबर होता था लेकिन अलकतरा खरीदी में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 93.7 प्रतिशत हो गया । उस समय के मंत्री अलकतरा बेच कर घोटाला किया करते थे, सड़क कहाँ से बनती जब अलकतरा ही आपूर्ति नहीं हो पाती तो सड़क कहाँ से बनती । महोदया, वहीं वर्ष 2005 में एन०डी०ए० सरकार बनने के बाद बिहार में सड़कों–नदियों पर पुलों का जाल बिछ गया, घंटों की दूरियां मिनटों में बदल गई है । ग्रामीण इलाके अब तक 1.17 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, वहीं अगर बिजली विभाग की बात करें तो उस समय की जो स्थिति थी लोग बिजली के लिए कराहते थे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे और आज वह स्थिति है बिहार में वर्ष 2005 के पहले की सरकार बिहार को लालटेन युग में ढकेल दिया था । लोग घर से शाम में चार बजे के बाद डर से निकलते नहीं थे, कब किस बहन–बेटी का अपहरण हो, हत्या, बलात्कार हो जायेगा, कोई अप्रिय घटना घट जायेगी, कोई नहीं जानता था । महोदया, वहीं एन०डी०ए० की सरकार बनने के बाद बिहार में बिजली की हालत अच्छी होने से बहन–बेटी.....

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपलोग शांति बनाये रखें । माननीय सदस्यगण, आपलोग शांति बनाये रखिये, उन्हें बोलने दिया जाय ।

श्री मुरारी मोहन झा : सत्येन्द्र जी भी उस समय की स्थिति को देखे होंगे । मगर अब करेंगे क्या यहाँ बैठे हुए हैं तो उनको पक्ष में बोलना ही न पड़ेगा ।

(व्यवधान)

बिजली की हालत और शाम चार बजे के बाद घूमने भी निकलती है क्योंकि एन॰डी॰ए॰ सरकार ने सस्ते दर पर राज्य के सभी गाँव और टोलों में 24 घंटा बिजली सुविधा प्रदान कर रही है ।

...क्रमशः...

टर्न–17 / संगीता / 05.03.2025

श्री मुरारी मोहन झा : (क्रमशः) वहीं महोदया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वर्ष 2005 से पहले की सरकार में स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर थी । अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, आम जनता उपचार कराने के लिए दर–दर भटक रहे थे । उपचार नहीं होने के कारण मरीजों को जान गंवाना पड़ता था, वहीं एन0डी0ए0 सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अद्वितीय विकास हुआ है । राज्य के सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर गरीब–गुरबा एवं पीड़ित परिवारों को स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है, असाध्य रोगों के उपचार हेतु अस्पताल का निर्माण कर डॉक्टर को पदस्थापित किया गया है ।

''जिंदगी अक्सर उन्हीं को चुनौती देती है जिनकी औकात होती है कुछ करने की ।''

महोदया, यह उस समय का इन लोगों का प्रचलित नारा था । इनके समय में...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए । आपका समय 2 मिनट है, आप संक्षिप्त कीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदया, 1990 से 2005 के कार्यकाल में 'भूरा बाल साफ करो' का नारा दिया करते थे, ये जातीय उन्माद फैलाने का काम किया करते थे, ये आज दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, मैं उनको चैलेंज

देता हूं कि उन्हीं का नारा दिया हुआ है 'भूरा बाल साफ करो' जातीय उन्माद बिहार में फैलाने का किसने प्रयास किया था महोदया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको बिहार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है महोदया । शिक्षा के बारे में बताऊं तो वर्ष 2015 से पहले की सरकार में जहां बहन–बेटियां घर में सुरक्षित नहीं थीं, निकल कर स्कूल नहीं जाना चाहती थी कि कब मेरा अपहरण हो जाएगा, पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही थी, तत्कालीन सरकार के द्वारा चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था, वहीं एन0डी0ए0 की सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहन–बेटियों को कैसे अच्छी शिक्षा प्रदान किया जा सके उसके लिए सुयोग्य शिक्षक कैसे घर से निकलकर विद्यालयों तक पहुंचे, उसके लिए साईकिल, पोशाक, कैसे गरीब परिवार के बच्चे भी उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा प्रदान कर, सारी नीति लागू कर शिक्षित किया और सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया जिस कारण बिहार की बेटियां भी बड़ी मात्रा में बिहार से बाहर भी सरकारी नौकरी एवं रोजगारों में अपनी पहचान बना रही है । महोदया, जो लोग अपने मनोरंजन के लिए गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन करते हैं उन्हें विधान सभा में गरीबों के हित के लिए पेश किए गए बजट फालतू ही लगेंगे महोदया...

(व्यवधान)

वह मिलेगा, मिलेगा, चिन्ता नहीं कीजिए । आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, वह मिलेगा 95 लाख परिवारों के बारे में जो घोषणा किए हैं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री मुरारी मोहन झा : वह सबको मिलेगा, आप घबराइए नहीं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, अपना पक्ष रखें ।

श्री मुरारी मोहन झा : एक मिनट महोदया, एक मिनट में समाप्त करते हैं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : नहीं, अब समाप्त किया जाय । अब समय समाप्त हो गया ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, बस एक दोहा मैं बोल देता हूं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी ।

श्री मुरारी मोहन झा : ''कस्ती चलाने वालों ने जब हार की दी पतवार हमें,

लहर–लहर तूफान मिले और मौज–मौज मझदार हमें

फिर भी दिखाया है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह जी अपना पक्ष रखें ।

श्री मुरारी मोहन झा : हमने और फिर वे दिखा देंगे सबको कि किन हालत में आता है...

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपका समय 19 मिनट है ।

श्री अजय कुमार सिंह : मुझको सरकार द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय पर बोलने का अवसर दिया है । माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके बजट में जो खामियां हैं उस ओर मैं इशारा करूंगा । विपक्ष का यही काम है कि आपके बजट की खामियों को उजागर करें, आपके समक्ष रखें । इस सूबे के पहले मुख्यमंत्री डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह के जमाने में बिहार पूरे देश में नंबर एक पर था लेकिन आज आप बीमारू राज्य के रूप में हैं । कांग्रेस के जमाने में 32 चीनी मिलें काम कर रही थीं । आज कुछ ही चीनी मिल आपके यहां काम कर रही है, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । सरकार रोजगार के अवसर का ढ़िढ़ोरा पिटती है किन्तु आज तक बिहार में एक वैसा आई0टी0 पार्क, जिसमें कई आई0टी0 कंपनियों का ऑफिस हो, नहीं बन पाया है । यहां के इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्र दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस राज्य में रोजगार के अवसर ही नहीं मिल पा रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी आप बैठे हुए हैं, बड़ी चर्चाएं होती हैं कि हमने इतनी नियुक्तियां कर डालीं । जब लोग नौकरी पाते हैं तो प्रशंसा होती है लेकिन आपने जो नियुक्तियां की हैं उसमें नियुक्त होने वाले शिक्षक आज भी दुखी हैं और आपका जो सिस्टम है वह कहता है कि हम जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं । एक ओर तो आप डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हैं दूसरी ओर आपके सॉफ्टवेयर बनाने में इतनी दिक्कतें आती हैं तो या तो डिजिटल इंडिया की चर्चा करना बंद कर दें । पहले इसको ठीक–ठाक कीजिए जो लोग दुखी से सुख की ओर लोग जाएं नियुक्त होने वाले, राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेंट आदि के कॉलेजों की संख्या बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है इसके बावजूद यहां पढ़ने वाले छात्रों को इस राज्य में रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वे अन्य राज्यों अथवा दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं । दूसरे राज्यों में डेढ़ सौ– दो सौ तक की संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं और वहां विनिवेश के कारण सबों को रोजगार मुहैया हो जाता है । अभी

उद्योग मंत्री जी थे यहां, चले गए, उद्योग मंत्री जी ने 2023 के अपने बजट भाषण में स्पष्ट उल्लेख किया था, संयोग से वे नहीं हैं । यह उनकी बात है कि राज्य में विनिवेश घटते जा रहे हैं । जो आपकी सरकार में कबीना मंत्री हैं, 20 वर्ष से एक ही सरकार है परन्तु विनिवेश के लिए सरकार कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं कर पायी है। महोदय, मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में माननीय वित्त मंत्री जी आप भी मौजूद थे, मैंने चर्चा किया कि अपने जिले मुंगेर में रेलवे का कारखाना है और उस कारखाने में मुंबई और कोलकाला से उसके छोटे–छोटे सामान आते हैं । यहां के व्यवसायियों से मिलकर उसकी लिस्ट बनाकर के यहां के व्यवसायियों से इसका उत्पादन कराएं जो वह माल कारखाने में जाए लेकिन पता नहीं इसका क्या हश्र होगा आपके सामने मैंने कहा था । सरकार के लोग यह बोलते रहते हैं कि फंलाने समय में बजट इतना था, अरे भाई, उस समय जो बजट था तो बाजार मूल्य का मूल्यांकन कहां से पाया, उस समय के रुपये का वैल्यू जो था, 7 हजार रुपये में 10 ग्राम सोना मिलता था और सोने से बाजार का कैल्कुलेशन होता था...

(क्रमशः)

टर्न–18 / सुरज / 05.03.2025

श्री अजय कुमार सिंह : (क्रमशः) और उस मूल्य के अनुपात में आज जो बाजार मूल्य है कि 90 हजार रुपये में 10 ग्राम सोना मिलता है । तो उस समय का 5 हजार हो या 4 हजार हो वह आज 4 लाख के बराबर है ।

महोदय, उस समय जी0एस0टी0 जैसा गड़बड़ टैक्स नहीं था । जी0एस0टी0 के माध्यम से राज्य के छोटे–छोटे व्यवसायियों की कमर तोड़ दी गयी । यहां तक कि बहुत सारे व्यवसायी अपना उद्योग–धंधा बंद कर चुके हैं । इस टैक्स का बोझ इन्डायरेक्ट रूप से आम जनता पर भी पड़ता है और जनता की गाढ़ी कमाई को वसूल कर केन्द्र से जो पैसा मिलता है उसी पैसे से यहां के कर्मियों का वेतन चलता है । एक–दो महीने यदि जी0एस0टी0 की वसूली कम हो जाए अथवा केन्द्र सरकार राशि मुहैया कराने में एक–दो महीने विलंब कर दे तो यहां की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पायेगी ।

महोदय, राज्य अपने संसाधन से धन इकट्ठा करने में पूरी तरह विफल रही है । बिजली के मामले में सुधार जरूर हुआ है परंतु राज्य में एक भी अपना बिजली घर नहीं है । दूसरे राज्य या केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है । कांग्रेस के जमाने में कई–कई थर्मल स्टेशन हुआ करते थे और सस्ते दर पर

निर्बाध बिजली भी मिलती थी । इससे पता चलता है कि यह राज्य सरकार कल्याणकारी राज्य नहीं होकर व्यवसायी राज्य हो गया है ।

महोदय, एक मेरे मित्र इधर से कह रहे थे कि धन्यवाद दे दीजिये । यह बिजली इसलिये मिल रही है कि जब परमाणु ऊर्जा पर समझौता अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, उस समय पार्लियामेंट में आपने विरोध किया था और सेंट्रल जोन से यू0पी0ए0 गवर्नमेंट ने अगर तमिलनाडु में बिजली पैदा होगी और बिहार में नहीं पैदा हो रही है तो तमिलनाडु की बिजली भी आपको मिलेगी । लेकिन उस समय आपने विरोध किया था और कहा था कि मनमोहन सिंह जी देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, जिसके लिये आज आप पीठ थपथपाते हैं कि बिजली हम पूरे राज्य को ठीक से दे रहे हैं । तो जब–जब गर्मी का दिन आता है, कई मित्र इसमें शहरी क्षेत्र के लोगों का फोन इंटरटेन करते होंगे और लोग कहते हैं कि हमारे यहां शट डाउन हो गया, दो घंटे बाद बिजली आयेगी । मतलब रोस्टर सिस्टम में बिजली चलती है । तो आप यह कैसे दावा कर सकते हैं कि आप 24 घंटे में 22 घंटे बिजली दे रहे हैं ।

माननीय वित्त मंत्री जी आप इस ओर ध्यान देना चाहेंगे, स्थिति तो यह है कि पटना में मेट्रो के लिये राशि के अभाव में निविदा भी जारी नहीं हो रही है, इसके लिये जापान से बार–बार अनुरोध के बावजूद भी ऋण नहीं मिल रहा है और मेट्रो के कई स्ट्रेच के काम ठप हैं । यह कैसी दो इंजन की सरकार है ? समझ में नहीं आ रही है बात क्योंकि यह प्रोजेक्ट राज्य और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर चला रही है ।

महोदय, ग्रामीण कार्य मंत्री आज ही सदन में बड़ी जोर से चर्चा कर रहे थे कि आपके विधान सभा में इतना किलोमीटर सड़क दे दिया, आपके विधान सभा में इतना किलोमीटर सड़क दे दिया । ग्रामीण कार्य मंत्री की मैं बात कर रहा हूं...

(व्यवधान)

नहीं, नहीं आज की मैं बात कर रहा हूं । पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं और इन सड़कों में आप कैसे बनायेंगे । कुछ सड़कों को अभी बनायेंगे, कुछ में मेंटेन करेंगे फिर उसको तीन साल बाद बनायेंगे । यह तो आपने कहा ही नहीं । यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के आलोक में आपने कहा कि इतनी सड़कें आपके यहां बना रहे हैं । 10 किलोमीटर सड़क है तो 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर ही आप बनाने जा रहे हैं, 5 किलोमीटर

तो आप मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, उसको बाद में बनाइयेगा । तो कहने का मतलब है कि सरकार को साफ–साफ बात करनी चाहिये ।

संयोग से ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हुये हैं, अभी नहीं थे आ गये । मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने जिले के हर कलेक्टर को यह चिट्ठी दिया है कि इंदिरा आवास में गड़बड़ी हो रही है ।

(व्यवधान)

यह मैं नहीं कह रहा हूं । यह सूबे का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है, अपने कलेक्टर को चिट्ठी दे रहा है । ग्रामीण विकास मंत्री जी आप इस पर संज्ञान लीजिये क्योंकि इसमें गड़बड़ी तो हो ही रही है । एक बात है...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, माननीय...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपलोग शांति बनाये रखिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, बात सही है कि पत्र लिखा गया है । हमने भी सभी माननीय सदस्यों को पत्र लिखा है कि ये सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है । यह 10 जनवरी से काम शुरू है और 31 मार्च तक सर्वेक्षण का काम चलेगा । जो आपके इलाके में, आपके गांव का है, आप इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिये । तो आपको पत्र लिखकर आगाह भी किये हैं कि आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिये और जहां गड़बड़ी की सूचना है वह हमारी सरकार तक पहुंचाइये तो उसमें जो गड़बड़ी है उसके हमलोग ठीक करेंगे ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय...

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो कहा...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय अजय कुमार सिंह जी आप अपनी बात जारी रखें, अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : लेकिन मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपलोगों से आग्रह है कि आपलोग बैठ जाएं, इनकी बात सुन लें ।

श्री अजय कुमार सिंह : आपका जो तंत्र है...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : नहीं, आपलोग बैठ जाइये । उनकी बात को सुन लिया जाए ।

श्री अजय कुमार सिंह : हवाला है, घोटाला है । समूचा निगल गये जब गाय तब क्या करेगा सी0बी0आई0...

(व्यवधान)

सत्यदेव भाई समय नहीं खराब करिये ।

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : सुनिये, आप अपनी बात अपनी बारी आने पर करियेगा । आपकी बारी आयेगी तो आप बोलियेगा ।

(व्यवधान)

उनको बोलने दिया जाए ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, अभी–अभी बिहार में बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा हुई है । इसमें दो बातें हैं । इसकी दो बार परीक्षा ली गयी है । एक बार 3 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा ली गयी है और एक बार 06 हजार विद्यार्थियों की परीक्षा ली गयी है । 03 लाख विद्यार्थियों में पासआउट होने का परसेंटेज 6 परसेंट है और 06 हजार विद्यार्थियों में पास होने का परसेंटेज 20 परसेंट है । एक चयन के लिये एक ही परीक्षा होनी चाहिये और इसके लिये संविधान भी इजाजत नहीं देता है । संविधान कहता है कि It is violation of article 14 and 19.

महोदय, जल संसाधन विभाग में जब कोसी को शापित नदी कहा जाता था तो इसके लिये देश के पहले प्रधानमंत्री ने इस शापित नदी को बांधने का काम किया था । इन्द्रपुरी बैराज जो सिंचाई के लिये सासाराम में है, वह बाबू जगजीवन राम जी ने इस योजना को बनवाया था और 22 डैम कांग्रेस के शासनकाल में बने थे । उसमें एक हनुमना डैम है, जिसका पानी माननीय वित्त मंत्री जी के खेत में भी जाता है । कुल मिलाकर इन्द्रपुरी बैराज, अभी कई

मित्रों ने कहा कि भारत में मैथिली के लिये कोई चर्चा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य अब संक्षिप्त किया जाए ।

श्री अजय कुमार सिंह : भारत की साहित्यिक अकादमी द्वारा मैथिली भाषा का दर्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1965 में शामिल कराया था ।

(क्रमशः)

टर्न–19/राहुल/05.03.2025

श्री अजय कुमार सिंह : (क्रमशः) आई0जी0आई0एम0एस0, जिस पर पीठ थपथपाई जा रही है इसका शिलान्यास ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था और उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय दिलकेश्वर बाबू थे । महोदय, जहां तक सवाल है शिक्षा के मामले में तो हम फिसड्डी हैं ही इसमें कोई दो राय नहीं है...

(व्यवधान)

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपका समय नहीं काटा जा रहा है । संक्षिप्त करने के लिए कहा गया है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदया, मैं दो मिनट में कंकलूड करता हूं । बड़ा–बड़ा बजट दिखायी देता है लेकिन इस बजट में मैं चर्चा करना चाहता हूं रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में जो ऑरिजनल प्रोविजन है उसमें एक्सपेंडिचर बहुत कम है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी जो ऑरिजनल प्रोविजन है उसमें 930 करोड़ ही खर्च हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग में 15320.04 करोड़ है जिसमें 12777.67 करोड़ खर्च है तो इस ढंग से यह 2021 का बजट है और 2022 के बजट में बड़ी चर्चा होती है, 2023 के बजट के 9 विभागों की मैं चर्चा कर देता हूं जिसमें शिक्षा के लिए 55892.37 करोड़ था जो मात्र 42095.78 करोड़ ही खर्च किया गया तो इतना बड़ा बजट लेते क्यों हो, ग्रामीण विकास का वही हाल है, स्वास्थ्य में तो 61.74 प्रतिशत खर्च हुआ है, गृह विभाग में 57.8 परसेंट है, ग्रामीण कार्य में 64.19 परसेंट है, पंचायती राज में पूरे बजट का 68.26 परसेंट है और नगर विकास एवं आवास विभाग में पूरे बजट का 55.22 परसेंट आपने खर्च किया तो बजट का आकार आप बड़ा क्यों बनाते हैं ? आप खर्च ही नहीं कर पाते हैं तो फिर आकार बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है । अब जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें कृषि विभाग में 1276.80 केन्द्र से लिये हैं और 321.96 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं तो आप जब केन्द्र के पैसे को भी खर्च नहीं करते, उपयोगिता प्रमाण पत्र आप नहीं देते तो फिर आपके पास पैसा

आयेगा कहां से, उसी तरह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की भी बात है । कल से बड़ा ढ़िंढोरा पीटा जा रहा है अनुसूचित जाति, जनजाति की चर्चा हो रही है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य अब समाप्त किया जाय ।

श्री अजय कुमार सिंह : इसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 से लेकर 2022–23 तक का हिसाब है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 22.24 परसेंट केन्द्र के पैसे का आप खर्च किये हैं तो आप कैसे अपने आप को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हितैषी मान रहे हैं, उसके पक्ष का भी पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो कुल मिलाकर के बराबर तोहमत लगायी जाती है कांग्रेस पार्टी पर, जब से यू0पी0ए0 गवर्नमेंट आयी है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : अब समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री अजीत जी अपना पक्ष रखें ।

श्री अजय कुमार सिंह : लगातार आपके लिए अनुदान की राशि हम बढ़ाते गये हैं कोई वर्ष ऐसा नहीं है जहां नहीं बढ़ाया है । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री अजीत जी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदया, कल माननीय वितमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया । हम लोगों ने पूरा बजट पढ़ा, जानते ही हैं हम लोग पढ़ने–लिखने वाले आदमी हैं, लाईन बाई लाईन पढ़ा, बहुत निराशाजनक बजट है, पूरे बिहार की जनता को हताश करने वाला बजट है । क्या है इसमें ? हमें लगा कि 70 तक अपनी उम्र में पहुंचने वाले मुख्यमंत्री जरूर अपनी उम्र के लोगों के लिए कुछ सोचे होंगे लेकिन अफसोस कि वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ायी गयी । मात्र 400 रुपये मिनिमम वेजेज से भी कम एक महीने में, यह बिहार की स्थिति है । देश में किसी भी राज्य में बुजुर्गों को इतनी कम पेंशन नहीं मिलती है । यह बिहार के बुजुर्गों का अपमान है । लंबे समय से मांग हो रही है कि वृद्ध के लिए, विधवा के लिए, विकलांग, दिव्यांगों के लिए कम से कम 3000 रुपये दिये जायं । कितना कम है, यह सोचने वाली बात है । सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह बजट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है । हमें लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है तो बहुत कुछ होगा। हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे, आर्थिक सर्वेक्षण में है कि लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 2023–24 में बिहार में दो लाख आवेदन आये जिसमें 40 हजार लोगों के आवेदन स्वीकृत किये गये और उनको पैसे दिये गये । पिछले समय जब महागठबंधन की सरकार थी तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण के बाद यह घोषणा हुई थी कि बिहार के 95 लाख ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 6000 रुपये से कम है उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जायेगा और उनको 2 लाख रुपया दिया जायेगा । महोदया, 95 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देना है और एक साल में 40 हजार लोगों को दिया गया । जरा हिस्सा जोड़िये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं,

कई सारे इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं गणित मुझे कम समझ में आती है, मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि 95 लाख परिवारों को देने में 236 वर्ष लग जायेंगे, यह दुनिया की अजूबी योजना है जिसके लिए 236 साल, पता नहीं आप रहें, हम रहें, कोई रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे पता नहीं । सभापति महोदया, इस बजट में किसी की बात नहीं सुनी गयी, पूरे बिहार में पिछले 2 साल से लोग मांग कर रहे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं है जैसे आशा, रसोइया बहनें, जिनको 1650 रुपया मिलता है, आशा जिनको कुछ नहीं मिलता, जीविका, ए0एन0एम0, जिनको मात्र दस हजार रुपया सैलरी मिलती है, ग्राम कचहरी सचिव, किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, वन कर्मी, चौकीदार, दफादार, बी0पी0एस0सी0 अभ्यर्थी, ग्रामीण चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारी और सहारा के जुल्म से बेसहारा हुए लोग, विधवा, विकलांग, दिव्यांग, मजदूर, किसान । इनके बारे में कुछ नहीं हुआ । जिनकी मांगें थी किसी को पूरा नहीं किया गया । महोदया, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय, महिला । रोज महिलाओं के बारे में बताते हैं कल भी कुछ बता रहे थे, आज भी बता रहे थे, एक दिन मैंने देखा विशिष्ट शिक्षकों को पत्र बांट रहे थे बोले हंसती काहे नहीं हो जी । अरे हंसो । हंसना नेचुरल प्रक्रिया है, हंसी आयेगी तो हंसेंगी, जबरदस्ती, मैडम आप बैठी हुई हैं हम बोलेंगे काहे नहीं हंसती हैं तो आप हंसने थोड़े लग जायेंगी, मेरी बात कोई अच्छी लगेगी तो आप हंसना शुरू करेंगी...

(व्यवधान)

यही विषय है । महिला विषय है । महोदया, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय है । उन्होंने कहा...

(व्यवधान)

जी बिल्कुल । महोदया, बहुत नाम लिया जाता है । बजट में कहा गया, बहुत पिंक–पिंक टाइप का नाम लिया गया जैसे पिंक टॉयलेट, पिंक बस, पिंक ये, पिंक मतलब क्या गुलाब समझते हैं ? सभापति महोदया, पूरे बिहार की महिलाएं अपने सवालों के लिए सड़क पर आंदोलनरत हैं, आप उनको उचित मानदेय नहीं दे रहे हैं । उन्होंने एलान किया है कि ''हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं'' और मैं दावे के साथ कह रहा हूं जिस तरीके से महिलाओं के श्रम का शोषण किया जा रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–20 / मुकुल / 05.03.2025

क्रमशः

श्री अजीत कुमार सिंह : आशा को, रसोइया को और अन्य महिला कर्मियों को उनको उचित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, ये औरतें एक दिन आयेंगी और अपनी अदालत में आपको खड़ी करेंगी और अपनी चिंगाड़ी से आपको भस्म करके खत्म कर देगी । वैसे भी अब यह आपलोगों के जाने का साल चल रहा है, चुनाव है कोई जायेगा तो कोई आयेगा यह तो स्वाभाविक है महोदय । किसानों के बारे में कहा गया, आपने दाल के बारे में कहा अच्छी बात है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी इस विषय पर कोई बात नहीं हुआ । महोदया, पहले से जिन फसलों पर एम0एस0पी0 मिलता है अगर उसको नहीं बढ़ाया जायेगा तो फिर किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी । देश में बिहार के किसानों को सबसे कम एम0एस0पी0 मिलता है, मजदूरों के बारे में, छात्र–नौजवानों के बारे में आपने न कोई मिनिमम वेज बढ़ाने की बात कही, मजदूरों के लिए बेहतर जिंदगी हो, उनका मान–सम्मान बढ़े इसके बारे में भी आपने कोई विशेष बात नहीं कही ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

महोदय, हमलोग लंबे समय से कह रहे हैं कि बिहार पलायन स्टेट के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गया, महोदय यह बिहार के लिए गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है कि देशभर में बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं । पहले आप इसको स्वीकार नहीं करते थे लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि हम कर्नाटका से लेकर, हैदराबाद से लेकर, दिल्ली और कलकत्ता तक प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केन्द्र बनायेंगे, ये आपकी बातें खुद कह रही हैं कि इस राज्य के लाखों मजदूर बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं । महोदय, प्री–मैट्रिक की छात्रवृत्ति बढ़ाने की बात हुई वह मुझे लगता है कि बहुत लुभावना वायदा है । अनुसूचित जाति/जनजाति वेलफेयर पर 2023–24 के बजट में 3 हजार 7 सौ 69 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, जिसमें इस सरकार ने मात्र 1 हजार 24 करोड़ रुपया खर्च किया, मात्र 27 प्रतिशत । सोचिए, कितना अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सरकार को चिंता है । महोदय, स्वास्थ्य की भी वही स्थिति है, कल मुख्यमंत्री जी कह रहे

थे पहले एक महीना में 29 मरीज आते थे, आजकल 11 हजार आते हैं । महोदय, हमारे यहां पी0एच0सी0 है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास दो ही मिनट का समय है ।

श्री अजित कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट काफी है, एक मिनट बढ़ा दीजिएगा तो ठीक है नहीं तो मैं दो मिनट में ही अपनी बातों को रख देंगे । महोदय, हमारे यहां जो पी0एच0सी0 है वहां मात्र 1 डॉक्टर है, मात्र एक कर्मचारी है । अब कोई ज्ञानी व्यक्ति बताये कि 1 डॉक्टर एक महीने में 11 हजार मरीजों का कैसे देख–रेख कर सकता है । इतना फर्जी आंकड़ा अधिकारी लोग सरकार को भेजते हैं, मैं तो वर्षों से मुख्यमंत्री जी से कहता रहा हूं लेकिन वे नहीं मानते हैं, अब उप मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी हैं इनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप यंग हैं, जरूर अधिकारियों के झूठ को पकड़िये, आपको ये असली आंकड़ा नहीं देते हैं । पिछले बजट सत्र में आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे और आपने मेरे ही सवाल के जवाब में यह सब कुछ लिखकर दिया है कि कहां कितने डॉक्टर हैं आपको लोग बता देंगे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक डॉक्टर एक महीने में 11 हजार मरीजों का इलाज नहीं कर सकता है । अध्यक्ष महोदय, पुरानी–पुरानी बातों में हमें यकीन नहीं हैं, हम तो जवाब हुए नीतीश जी के शासनकाल में । महोदय, 2005 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री बने, मेरे उम्र के जितने नौजवान होंगे, यहां कई लोग हैं वे सब उसी समय जवान हो रहे थे महोदय । हमने नीतीश कुमार जी का वह रोबदार चेहरा भी देखा, जब रेल मंत्री हुआ करते थे, एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने रिजाइन दे दिया वह नीतीश कुमार । महोदय, वह नीतीश कुमार जब बिहार में 2013 में मुख्यमंत्री थे, जब गुजरात से नरेंद्र मोदी को देश में लाया गया तो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया और कहा कि बिहारी हैं हम, गुजरात के व्यापारियों का राज बर्दाश्त नहीं करेंगे । महोदय, बिहार का अपना एक गुरूर है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अजित कुमार सिंह : महोदय, एक मिनट । महोदय, बिहार की अपनी प्रतिष्ठा है...

अध्यक्ष : अजित जी, मेरी बात सुनिये । एक तो आपकी पार्टी में एकता नहीं है । आपकी पार्टी के दो नेता ने, दो लोगों का नाम......

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय,......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : केशरी जी, शांत रहिये, बैठिये ।

श्री अजित कुमार सिंह : महोदय....

अध्यक्ष : आपकी पार्टी के दो नेता ने दो–दो लोगों का नाम दे दिया ।

श्री अजित कुमार सिंह : महोदय नहीं, एक ही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास कागज है ।

श्री अजित कुमार सिंह : महोदय, वह मेरा ही है दोनों ने दो तरह का नाम इसमें दे दिया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास नाम है, आपका समय समाप्त हो गया है अब आप बैठ जाइये ।

श्री अजित कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक शेर सुन लीजिए । महोदय, बस एक शेर । कल बर्बस मुंह में आ गया तो मैंने याद कर लिया तो मैंने सोचा की आपको जरूर सुनाऊंगा महोदय ।

अध्यक्ष : अब तक तो आप बोल चुके होते ।

श्री अजित कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल जब बजट समाप्त हो रहा था, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी.....

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान जी आप बोलिये ।

श्री अजित कुमार सिंह : महोदय, बस एक शेर है ।

''कोई हाथ भी न मिलायेगा, जो गले मिलोगा तपाक से,

ये नये मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो ।''

अध्यक्ष : अखतरूल ईमान जी, आप बोलिए । आपके पास एक मिनट का समय है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि विद्वान और बलवान मंत्री जो बजट पेश करेंगे और 20 साल पुरानी सरकार का बजट होगा, यकीन था कि काया पलटने वाला बजट होगा । लेकिन बड़ी निराशा आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म अब तक नहीं हो सका, पूर्णिया को उप राजधानी और हाईकोर्ट बेंच मुतालबा था, इस पर बिल्कुल खामोशी छाई रही, वृद्धा पेंशन के बारे में मुझे याद है जब वर्ष 2006 में मैं आया था 27 हजार करोड़ का बजट था, आज 15 गुना लगभग बजट बढ़ा है लेकिन गरीबों को, विकलांगों का पेंशन आज भी 300, 400 और 500 रुपये है, उनको 3,000 किया जाय यह मैं उन गरीबों की मांग रख रहा हूं । महोदय, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार जब कृषि बजट में कटौती करती है तो किसानों का उत्थान नहीं कर सकती है । प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्प डेस्क की बात इन्होंने कही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के बच्चों का क्या हाल है उसके बारे में सरकार ने कोई वेल्फेयर स्कीम की बात नहीं की है । सिंचाई का मामला बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । एम0एस0डी0पी0 जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना है वह पिछले 5, 7 सालों से बंद पड़ा है । माइनोरिटी स्कॉलरशिप को नहीं बढ़ाया गया है और 2013 के नियमावली के अनुसार एक साल के अंदर में वक्फ का सर्वे कराया जाना था लेकिन इस सरकार ने उस सिलसिले में भी कोई कदम नहीं बढ़ाया है, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, पलायन मजदूरों के अधिकार का हनन हुआ है ।

अध्यक्ष : डॉ सत्येन्द्र यादव ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक शेर पढ़ना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : डॉ सत्येन्द्र यादव, आपके पास दो मिनट का समय है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, सबने एक शेर पढ़ा है, मैं भी एक शेर पढूंगा ।

अध्यक्ष : फिर कभी बोलियेगा । डॉ सत्येन्द्र यादव, बोलिए ।

डॉ सत्येन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025–26 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है उस बजट को गंभीरता से स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 3 लाख 17 हजार करोड़ का जो बजट है उस बजट में स्कूलों में काम करने वाली रसोइया जो 1600 रुपया में 1 महीना काम करती है, उसकी वृद्धि के लिए कोई इंतजाम नहीं है । पंचायतों में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने वाले स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक के जो मानदेय 3 हजार है उसकी बढ़ोतरी की कोई बात नहीं है । आशा, ममता, जीविका का मानदेय जो 18 हजार रुपया होना चाहिए उनके मानदेय की बजट में कोई चर्चा नहीं है । मैं चर्चा करना चाहता हूं हासिये पर खड़े जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत के जो लोग हैं, उनके जो बिजली बिल हैं, वह बिजली बिल इस कदर बढ़ रहे हैं और बिजली बिल नहीं देने पर एफ0आई0आर0 होता है और जबरन फाइन करके बिजली के जो अधिकारी लोग हैं वे वसूली कर रहे हैं । माननीय बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका आधा मिनट बचा हुआ है ।

डॉ सत्येन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्री का जो बिजली है, जिस चक्रवृद्धि ब्याज से उनके बिल बढ़ रहे हैं, आज लाखों–लाख रुपया का बिल गरीबों का कट रहे हैं, सभी माननीय विधायकों के पास गरीब जाते हैं, माननीय विधायक लाचार हैं, जबरन पुलिस के दम पर वसूली किया जा रहा है और वसूली नहीं होने पर जेल भेजा जा रहा है । यही तो माननीय नीतीश कुमार का यह 20वां बजट का देन है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट एन0डी0ए0 की सरकार लाई है वह बजट कहीं से आशा, ममता, जीविका, महिलाओं, छात्र, नौजवानों और किसानों के हित में यह बजट नहीं है ... XXX

टर्न–21/यानपति/05.03.2025

अध्यक्ष : समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य, श्री राज कुमार सिंह ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ग्रामीण कार्य मंत्री के बारे में कह रहे हैं इनके पास कोई प्रमाण है, सवाल सदन में उठा रहे हैं, अगर प्रमाण नहीं है तो इनको इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये सत्येंद्र जी । सत्येंद्र जी बैठिए । बोलिए राजकुमार जी ।

श्री राज कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और......

अध्यक्ष : राजकुमार जी, एक मिनट । माननीय मंत्री जी बोलना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री श्रवण जी ने जो उठाया है, यह इस सदन की परंपरा का प्रश्न है, इसी आसन से कई बार निर्णय हो चुका है कि इस सदन के मंत्री ही नहीं किसी सदस्य के विरुद्ध भी अगर कोई व्यक्तिगत आरोप आक्षेप लगाना हो तो पहले सबूत दिखाकर आपसे इजाजत ले ली जाती है तब सदन में उसका उल्लेख किया जाता है और अगर आपसे इजाजत लेकर हुआ है तब ठीक है वरना इसको सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, हम देख लेंगे ।

XXX आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

श्री राज कुमार सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भी आज आय–व्यय पर बोलने का मौका मिला । मैं कल से ही देख रहा हूं कि इस सदन में कालखंडों का कंपेरिजन लगभग सभी लोगों ने किया है और शुरूआत माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हुआ तो इस संक्रमण से मैं भी अपने–आप को बचा नहीं पा रहा हूं । उन्होंने 1990 से पहले की बात की, जब 1990 से पहले की बात हुई तो मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूं । अध्यक्ष महोदय, I have just recalled something

because I have been a student of History. So I started comparing Bihar 1990 and 2005 with the medieval ages of 15th century after the fall of Roman Empire. The entire age was marked with declining law & order, rampant corruption, breakdown of social machinery everywhere there was chaos and that is the scene which we witnessed in Bihar during the period and the result was exodus. Exodus of not only paid on trade & commerce of aspiring students, youth who wanted employment and result after exodus and after going to Delhi, Bombay, Madras everywhere those economies acronyms that were tributed to the word Bihari. This was all because of the period that witnessed Bihar during 1990 & 2005.

एक और, One of the most classic example of this period, in that period Lords used to ask for land for military service that was very liberty on those things and years we have all seen land for Government services this is very similar to the period of those dark ages of medieval year.

अब मैं कहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से बिहार को बदनामी और गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालने का काम एक व्यक्ति ने किया जिसपर बिहार ने विश्वास किया बिहार की जनता ने, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है और इस परिस्थिति से जब मैं देखता हूं तो मुझे जयशंकर प्रसाद की एक कविता याद आती है कि

''वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या

जिस पथ में बिखरे शूल न हों

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या धाराएं यदि प्रतिकूल न हों ।

वह पथ था बिहार की वह परिस्थति 1990 से 2005 की और वह पथिक नीतीश कुमार जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए उस 23 हजार करोड़ के बिहार को आज 3 लाख 17 हजार करोड़ का बिहार बनाया और देश की सबसे तेज गति से चलनेवाली आर्थिक व्यवस्था भी बनाया । यह पूरा सम्मान न सिर्फ उनका दूरदर्शी नेतृत्व रहा है बल्कि इसमें जो हमारी डबल इंजन की सरकार रही है केंद्र की सरकार, एन0डी0ए0 के माननीय

प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व जो बिहार को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है और आज देश में कहीं पर भी हम जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ बिहारी होने का सम्मान पाते हैं ।

आज इस बजट में जितनी बातें कही गई हैं मैं तो इतना ही कहूंगा चूंकि पांच मिनट का ही समय आपने दिया है न्याय के साथ विकास और इस न्याय के साथ विकास में सबसे पहला जो काम था, जो चैलेंज था जब सरकार आई उस वक्त था कि यहां पर कानून व्यवस्था को स्थापित करना और उसके लिए यहां पर मात्र 42 हजार यहॉ पर पुलिसकर्मी थे उसकी संख्या को बढ़ाकर 1 लाख 10 हजार किया गया । सिर्फ 814 थाने थे आज 1380 थाने हैं इस राज्य में और महिलाओं की संख्या तो हम सब जानते हैं । पुलिस की नौकरी में आज 30 हजार से अधिक है जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है । यह महिला उत्पीड़न, महिलाओं को भी न्याय दिलाने के लिए यह एक बहुत ही दूरदर्शी पहल है माननीय नीतीश कुमार जी की और उसी को देखते हुए लगातार महिलाओं को नौकरियों में जो 2016 के बाद जो सभी नौकरियों में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया, यह आधी आबादी के लिए न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि उनको सशक्त करके बिहार के हर परिवार को एक उन्नत परिवार, एक समृद्ध परिवार बनाने की दिशा में उनका कार्य है । उन्होंने यह कार्य बखूबी लगातार किया है और आज प्रगति यात्रा के माध्यम से आज तमाम जिलों में जाकर जिस तरीके से योजनाओं का निरीक्षण एक मुख्यमंत्री जिले में जाता है तो अपनी पॉलिटीकल एक्टिविटी के लिए नहीं जाता है । वह तो स्वतः मिलता है उसका माइलेज लेकिन जब वह मुख्यमंत्री हर साल अपने जिले में किसी न किसी यात्रा के माध्यम से सरकार की चल रही योजनाओं का निरीक्षण करता है तो लगता है कि बिहार सचमुच में एक अच्छे हाथ में है और बिहार इसी हाथ में आने वाले समय में 2025 से 2030 के बीच में भी रहेगा और बिहार की प्रगति और हमलोग एक अग्रणी राज्य के रूप में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं यह नहीं कहूंगा कि आज शिक्षा पर 60 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बजट दिया गया है, स्वास्थ्य पर 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बजट दिया गया है । ग्रामीण विकास विभाग पर 16 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बजट है । ये तमाम चीजें जो हैं जो लोग चर्चा करते हैं कि हमारा ह्यूमन इंडेक्स में हम काफी नीचे हैं, हां हम नीचे है ।

अध्यक्ष : केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये ।

श्री राज कुमार सिंह : हां, इस नीचे रहने की वजह भी आप ही लोग हैं जिन्होंने बिहार को 15 साल तक इतने गर्त में डाला कि उससे बाहर निकलने में जिस तरीके के

उद्योग जिस तरह के उद्यम की आवश्यकता होती है वह हमलोग करते आ रहे हैं लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि हम सबकुछ कर चुके हैं ।

चूंकि एक मिनट का ही आपने समय दिया है तो मैं अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में कहूंगा क्योंकि संबंधित मंत्री जी भी हमारे यहां पर है । मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री, जल संसाधन भी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी से आग्रह होगा कि बाढ़ से स्थायी निदान के लिए रिंग बांध की निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ी और तेजी लाई जाए ताकि लोगों को स्थायी निदान मिले और साम्हो एवं मटिहानी के बीच जो प्रस्तावित पुल है उसके निर्माण के लिए भी उस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार और संबंधित केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया जाए और इस बीच में साम्हो, मटिहानी के बीच में एक पीपापुल का निर्माण करा दिया जाए ताकि वहां के लोगों को आवागमन और अन्य सुविधाएं मिलें । मैं समय का पाबंद भी रहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री राज कुमार सिंह : मैं अटल जी की एक कविता की चार पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि अभी हमारा मार्ग लम्बा है ।

''आहुति बाकी यज्ञ अधूरा,
अपनों के विघ्नों ने घेरा,
अंतिम जय का वज्र बनाने
नव दधीचि हड्डियां गलाएं
आओ फिर से दिये जलाएं ।

बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सब लोग जो कविता कह रहे हैं तो मेरा भी कवि हृदय जाग रहा है लेकिन आज नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे, बैठिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप आसन से इतने सदस्यों की शेरो–शायरी सुनते हैं कुछ आसन सुना देता तो समझिए पूरा सदन उपकृत महसूस करता ।

अध्यक्ष : सुना देंगे, लेकिन आज नहीं सुनायेंगे । माननीय सदस्यगण, बजट पर वाद–विवाद कल दिनांक–06 मार्च, 2025 को भी जारी रहेगा ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–05 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–28 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार दिनांक–06 मार्च, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।